

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com



पृष्ठ 3

जल्द होगा उर्वरक नीति में सुधार

निर्मला सीतारमण पृष्ठ 4

साल में एक ही बार बदली जाएं जीएसटी दरें



बिज़नेस स्टैंडर्ड
वार्षिक
पुरस्कार
2019



**लाइफ टाइम
अचीवमेंट**

अजीम प्रेमजी
संस्थापक, चेयरमैन, पिप्री



**सीईओ
ऑफ द इयर**

भास्कर भट्ट
पूर्व एमडी, टाइटन कंपनी



**कंपनी
ऑफ द इयर**

लार्सन एंड टुब्रो
एसएन सुब्रमण्यन, सीईओ एवं एमडी



**स्टार
एमएनसी**

नेस्टले इंडिया
सुरेश नारायणन, सीएमडी



**स्टार्टअप
ऑफ द इयर**

विग वास्केट
हरि मेहन, सीईओ



**स्टार
पीएसयू**

इंद्रप्रस्थ गैस
ईएस रंगनाथन, एमडी



**स्टार
एसएमई**

विनती ऑर्गेनिकस
विनोद सराफ

कारोबार के आकाश पर चमकते 'सितारे' सात

जाने-माने निर्णायकों ने भारतीय उद्योग जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वालों के नाम पर लगाई मुहर



(बाएं से दाएं) बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के चेयरमैन अमित चंद्रा, ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी, केकेआर इंडिया के सीईओ संजय नैयर, ओमिडियार नेटवर्क इंडिया की एमडी रुपा कुडवा, आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला (जूरी चेयरमैन), सिरिल अमरचंद मंगलदास में मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्राफ और जेएसडब्ल्यू समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल। मैकिंजी एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर नोशिर काका (सीई) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए।



बीएस संवाददाता
मुंबई, 9 फरवरी

टाइटन कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब 1.13 लाख करोड़ रुपये है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) के बाद वह टाटा समूह की दूसरी सबसे कीमती कंपनी बन गई। घड़ियों की रिटेल शृंखला से कारोबार शुरू करने वाली टाइटन कंपनी आज भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है और इसकी बिक्री तथा मुनाफे में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले तीन साल में इसकी शुद्ध बिक्री 20.6 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर से और शुद्ध मुनाफा 27.7 फीसदी सालाना की दर से बढ़ा है।

टाइटन समूह के इस कार्यालय का सेहरा कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक भास्कर भट्ट के सिर ही बांधा जाता है, जो करीब 17 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद अक्टूबर 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं। 2002 में जब उन्होंने कंपनी की कमान संभाली थी तब टाइटन काफी

ज्यादा कर्ज, सुस्त बिक्री और कमजोर मुनाफे से जूझ रही थी। कारोबार में नई जान फूंकने की उनकी रणनीति कारगर रही और परिचालन से नकदी की आमद तेज हो गई। शेयर बाजार में भी कंपनी का मूल्यांकन बेहद तेजी से बढ़ा। अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद तीन साल से भी कम समय में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की ऑर्डर बुक 3 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एलएंडटी ने सबसे पछाड़ते हुए वित्त वर्ष 2019 में 18 फीसदी तेजी के साथ सभी अनुमानों से बेहतर आय अर्जित की। निजी निवेश धीमा रहने के बाद भी उस वित्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध मुनाफा करीब 21 फीसदी बढ़ा। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कंपनी ने उसी साल आईटी कंपनी माइंडट्री का अधिग्रहण भी कर डाला।

बिज़नेस स्टैंडर्ड कॉरपोरेट उत्कृष्टता अवार्ड 2019 के लिए प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल के सदस्यों की बैठक में भास्कर भट्ट और एलएंडटी

की असाधारण उपलब्धियों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता था। मुंबई में 6 फरवरी को हुई निर्णायक मंडल की बैठक में दो अग्रणी कारोबारी समूहों के प्रमुख, दो प्राइवेट इक्विटी फंड के प्रमुख, दो वैश्विक प्रतिष्ठित प्रबंधन सलाहकार संगठन, सामाजिक प्रभाव डालने वाले एक अग्रणी निवेशक और एक प्रतिष्ठित कानूनी दिग्गज शामिल थे।

आठ सदस्यीय निर्णायक मंडल की अध्यक्षता आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने की। जेएसडब्ल्यू समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल, केकेआर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी संजय नैयर, ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी, ओमिडियार नेटवर्क इंडिया की प्रबंध निदेशक रुपा कुडवा, मैकिंजी एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर नोशिर काका, सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्राफ और बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी इंडिया के चेयरमैन अमित चंद्रा बतौर सदस्य शामिल थे।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

एक नज़र

आर्थिक आंकड़े, कोरोना तय करेंगे बाजार की दिशा

औद्योगिक उत्पादन तथा थोक एवं खुदरा महंगाई के आंकड़ों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम और चीन में कोरोनावायरस के संक्रमण से जुड़ी गतिविधियां इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल तय करेंगी। इस सप्ताह बुधवार को औद्योगिक उत्पादन तथा खुदरा महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। इनके बाद शुक्रवार को थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होंगे। पिछले सप्ताह शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हुआ। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 11 फरवरी को आने हैं। निवेशकों की निगाहें वैश्विक बाजारों पर भी रहेंगी।

आज का सवाल

क्या दूरसंचार क्षेत्र के कर्ज से बढ़ेगी बैंकों की मुश्किल?

www.bshindi.com पर राय भेजें। आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का जवाब

क्या व्हाट्सएप पे के आने के बाद हाँ **75.00%**
शुगतान खंड में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा? नहीं **25.00%**

पुर्जों पर शुल्क बढ़ने से महंगी होंगी कारें

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 9 फरवरी

वाहन कलपुर्जों के लिए आयात शुल्क में कोई भी वृद्धि पहले से ही दबाव डेल रहे वाहन उद्योग की परेशानी को और बढ़ा सकती है। बिक्री के मोर्चे पर वाहन कंपनियों की रफ्तार पिछले डेढ़ साल से सुस्त है और कंपनियों उससे उबरने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी कैटालिटिक कनवर्टर और अन्य पुर्जों एवं धातुओं के आयात पर शुल्क बढ़ाने के सरकार के निर्णय से अर्चभित हैं। उनका कहना है कि इससे बीएस6 वाहनों की कीमतों में आगे और इजाफा होगा।

सरकार ने कैटालिटिक कनवर्टर, वाहनों के विभिन्न कलपुर्जों और धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जिससे बीएस-6 वाहनों की लागत 5 से 7.5 फीसदी के दायरे में बढ़ जाएगी। इसके अलावा सरकार ने कनवर्टर के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे सेरामिक्स, स्टेनलेस स्टील एवं अन्य धातुओं पर भी आयात शुल्क में इसी तरह का इजाफा किया है। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी

के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी केनिच अयुकावा ने कहा, 'मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन कीमती सामग्रियों पर शुल्क में इजाफा क्यों किया गया है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इससे उत्पाद की लागत बढ़ जाएगी।' कैटालिटिक कनवर्टर विशेष तौर पर बीएस-6 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों के लिए एक आवश्यक उपकरण है क्योंकि यह वाहनों से हानिकारक उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। बीएस-4 से बीएस-6 में बदलने से पहले ही वाहनों की कीमतें बढ़ गई हैं और अधिकारियों को चिंता है कि इससे मांग में सुधार आने में देरी हो सकती है। वाहन विनिर्माताओं का संगठन सायम के अनुसार बीएस-4 से बीएस-6 में बदलने से वाहनों की कीमतों में औसतन 10 फीसदी का इजाफा होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी पवन गोयनका ने कहा, 'बीएस-6 वाहनों में कई ऐसे पुर्जे लगते हैं जिन पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। इससे लागत और बढ़ जाएगी।' टाटा मोटर्स के मुख्य कार्याधिकारी गुंटेर बट्सचेक ने भी कहा कि शुल्क बढ़ाने से ग्राहकों पर इसका बोझ पड़ेगा।

दूरसंचार में कर्ज.. प्रावधान की ताक़ीद

रघु मोहन
नई दिल्ली, 9 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनौपचारिक तौर पर बैंकों को दूरसंचार क्षेत्र में मानक और अन्य निवेश को लेकर अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत की ताक़ीद की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े कर्ज के गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित होने की काफी आशंका है। उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर, 2019 के आदेश के बाद आरबीआई की ओर से दूरसंचार क्षेत्र के कर्ज के बारे में यह पहला कदम है। अदालत ने समायोजित सकल राजस्व के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क बकाया चुकाने का आदेश दिया है।



- दूरसंचार क्षेत्र में बैंकों के लगे हैं करीब 4 लाख करोड़ रुपये
- आरबीआई ने मानक और अन्य कर्ज को लेकर अतिरिक्त प्रावधान पर विचार करने के लिए संकेत
- बैंकों ने अभी इन खातों को एनपीए में नहीं किया है वर्गीकृत

रकम को जोखिम नहीं है। कुछ का कहना है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जोखिम में हो सकता है, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी कर्ज है, जो दिवालिया प्रक्रिया में है। एक बैंकर ने कहा, 'हम विशिष्ट खातों और उसे किस तरह से पुनर्गठित करें, उसकी बात कर रहे हैं। एक ही खाते में ऐसा भी हो सकता है कि कंसोर्टियम के कुछ बैंक बेहतर स्थिति में हों।'

केंद्रीय बैंक द्वारा अतिरिक्त प्रावधान की ताक़ीद रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मामले में लागू हो सकते हैं। एक अन्य बैंकर ने कहा, 'वोडाफोन के मामले में हमें ज्यादा प्रावधान करना पड़ सकता है जबकि इसे अभी एनपीए में वर्गीकृत नहीं किया गया है।' आईडीएफसी बैंक ने 2018-19 की तीसरी तिमाही में 1,622 करोड़ रुपये के कर्ज का 50 फीसदी का प्रावधान किया था। इसकी वजह से उस तिमाही में बैंक को 1,639 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा। अब सबकी नज़रें वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने वाले भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले कंसोर्टियम की अगली बैठक कर टिकी है। इससे पता चलेगा कि बैंक दूरसंचार क्षेत्र में अपने निवेश पर किस तरह आगे बढ़ते हैं।

संक्षेप में

भारतीय कंपनियों का विदेशी कर्ज दिसंबर में घटा

भारतीय कंपनियों का विदेशी कर्ज पिछले साल दिसंबर में सालाना आधार पर 45 फीसदी घटकर 2.09 अरब डॉलर पर आ गया। यह दिसंबर 2018 में 3.81 अरब डॉलर रहा था। इसमें मसाला बॉन्ड के जरिए जुटाया गया 3.7 करोड़ डॉलर का कर्ज भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2019 में घरेलू कंपनियों ने 1.2 अरब डॉलर का कर्ज बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के स्वतः मंजूरी मार्ग से जुटाए। मंजूरी मार्ग से 84 करोड़ डॉलर का बाह्य वाणिज्यिक कर्ज जुटाया गया। शेष 559.8 लाख डॉलर का कर्ज रुपए के मूल्य वाले बॉन्ड (आरडीबी) जारी कर जुटाए गए। महीने के दौरान ईसीबी के स्वतः मंजूर मार्ग से एचपीसीएल–मित्तल पाइपलाइन ने 26.25 करोड़ डॉलर, एचडीएफसी क्रेडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10 करोड़ डॉलर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 20 करोड़ डॉलर और टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10 करोड़ डॉलर जुटाए।

भाषा

एफपीआई ने किया 5,177 करोड़ रु. का शुद्ध निवेश

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने लगातार छठे महीने खरीदारी का सिलसिला जारी रखते हुए फरवरी में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध रूप से 5,177 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ऋणपत्र श्रेणी को इसमें बहुलांश हिस्सा मिला है। डिर्पॉजिटी के आंकड़ों के अनुसार, 3 फरवरी से 7 फरवरी के दौरान एफपीआई ने ऋणपत्रों में 6,350 करोड़ रुपये लगाए। हालांकि शेयरों से उन्होंने इस दौरान 1,172.56 करोड़ रुपये की निकासी की। इस तरह आलोच्य अवधि में वे 5,177.44 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेशक रहे।

भाषा

पेट्रोल, सीएनजी पर ध्यान दे रही मारुति

प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजूकी डीजल इंजन वाले वाहनों का उत्पादन बंद करने के फैसले से बिक्री को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल मॉडलों और सीएनजी विकल्पों पर ध्यान दे रही है। कंपनी ने पिछले सप्ताह आंदे एक्सपो में कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) विटारा ब्रेजा का पेट्रोल मॉडल प्रदर्शित किया। अभी तक इसका सिर्फ डीजल इंजन मॉडल ही उपलब्ध था। कंपनी एस–क्रॉस का पेट्रोल संस्करण भी लाने की तैयारी में है। मारुति सुजूकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, हमें उम्मीद है कि डीजल इंजन के बंद होने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पेट्रोल संस्करणों की संख्या बढ़ाकर कर लेंगे।

भाषा

आर्सेलर–निप्पॉन को तेजी की आस

बाजार में मंदी के बावजूद आर्सेलरमित्तल–निप्पॉन स्टील का नजरिया तेजी का

इंशिता आयान दत्त
कोलकाता, 9 फरवरी

भारत के इस्पात क्षेत्र में भले ही नरमी दिख रही हो लेकिन प्रमुख वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल एंड निप्पॉन स्टील (एमए/एनएस इंडिया) का नजरिया तेजी का है। कंपनी ने एस्सार स्टील में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष और आर्सेलरमित्तल यूरोप के ग्रुप सीएफओ एवं सीईओ आदित्य मित्तल ने विश्लेषकों से बातचीत में कहा, ‘मध्यम से दीर्घाधि आधार पर वृद्धि की रफ्तार स्थिर रहेगी।’ आदित्य एएम/एनएस इंडिया के चेयरमैन भी हैं। वह एस्सर स्टील के अधिग्रहण पर विश्लेषकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या संयुक्त उद्यम वास्तव में शेरधारकों के लिए नकदी रिटर्न सुजित करेगी। दिसंबर के मध्य में आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील ने संयुक्त रूप से दिवालिया समाधान प्रक्रिया के जरिये एस्सार स्टील का अधिग्रहण किया था।

संयुक्त उद्यम में 60 फीसदी हिस्सेदारी आर्सेलरमित्तल की है जबकि शेष हिस्सेदारी निप्पॉन स्टील की। बाद

कोरोनावायरस से प्रभावित हो सकता है भारतीय फार्मा उद्योग

भाषा

नई दिल्ली, 9 फरवरी

भारतीय दवा कंपनियों की निगाह चीन में कोरोना वायरस की वजह से सक्रिय औषधि अवयवों की आपूर्ति पर पड़ने वाले असर पर है। वित्त वर्ष 2018–19 में चीन की दवा अवयवों के कुल भारतीय आयात में 67.56 फीसदी हिस्सेदारी थी। मूल्य के हिसाब से यह 240.54 करोड़ डॉलर बैठता है। यदि चीन में हालात में जल्द सुधार की शुरुआत नहीं हुई तो घरेलू दवा उद्योग पर इसका असर पड़ सकता है।

इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा, सभी कंपनियां स्थिति की निगरानी कर रही हैं। सरकार भी मामले से अवगत है और सभी पक्ष स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में स्थिति में हो रही प्रगति, महत्त्वपूर्ण सक्रिय अवयवों के भंडार आदि पर कड़ी निगाहें रखी जा रही है तथा उन वैकल्पिक स्रोतों को तलाशा जा रहा है, जहां से चुनिंदा अवयवों को मंगाने के लिए नियामकीय मंजूरियां मिल सकती हैं। जैन ने कहा, भारत एंटीबायोटिक्स और विटामिन जैसे अवयवों को लेकर आयात पर निर्भर है। कंपनियां इन अवयवों का दो–तीन महीने का भंडार बनाकर रखती हैं।

दवा कंपनी सनोफी इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, अभी कोरोना वायरस के पड़ सकने वाले असर का अनुमान लगा पाना जल्दबाजी होगा। हम आपूर्ति में कोई बाधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की करीबी से निगरानी कर रहे हैं।

एम/इंडिया का प्रदर्शन

■सालाना उत्पादन रफ्तार 74 लाख टन पर
■एबिटा रन रेट 60 करोड़ डॉलर पर
■कंपनी का नकदी प्रवाह सकारात्मक
<i>(जनवरी 2020 के लिए वार्षिक अनुमान)</i>

में संयुक्त उद्यम का नया नाम एएम/एनएस इंडिया रखा गया।

आदित्य ने जिस वृद्धि की ओर इशारा किया है वह भारत के लिए है। उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि भारत को लेकर खबरें नकारात्मक हैं जैसे वाहनों की मांग में तेजी से गिरावट आ रही है। लेकिन भारत में इस्पात की

खपत वास्तव में 2019 में करीब 4 फीसदी बढ़ी। हमारा मानना है कि 2020 में यह कहीं अधिक दमदार रहेगी।’

आदित्य ने कहा, ‘हम वृद्धि दर्ज करना चाहते हैं क्योंकि भारत में बाजार बढ़ रहा है। साथ ही हम बाजार में सुजित मूल्य को भी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैं इसे मूल्य के तौर पर

निर्यात के मोर्चे पर दवा कंपनियों में दम

सोहिनी दास

मुंबई, 9 फरवरी

अमेरिकी औषधि नियामक यूएसएफडी की सख्ती के बावजूद भारतीय औषधि कंपनियां चालू वित्त वर्ष के दौरान पिछले वित्त वर्ष (2018–19) के निर्यात लक्ष्य को पार करने के लिए तैयार हैं। औषधि निर्यात संवर्द्धन परिषद (फार्मेक्सिल) के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020 की अप्रैल से दिसंबर की अवधि में औषधि निर्यात में 11.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर तिमाही खासतौर पर भारतीय औषधि कंपनियों के लिए अच्छा रहा और इस दौरान 14.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.69 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। फार्मेक्सिल के महानिदेशक उदय भास्कर का मानना है कि मार्च तिमाही में भी वृद्धि की यही रफ्तार जारी रहेगी। यदि यही रफ्तार जारी रही तो चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात 22 अरब डॉलर को छू जाएगा। भास्कर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 में अब तक 15.5 अरब डॉलर का निर्यात हुआ जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11.5 फीसदी

डॉ रेड्डीज की वृद्धि योजना के केंद्र में भारत, उभरते बाजार

बीएस संवाददाता

हैदराबाद, 9 फरवरी

प्रमुख औषधि कंपनी डॉ रेड्डीज का कहना है कि वह वृद्धि के लिए उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। इन उभरते बाजारों में भारत, रूस और स्वतंत्र राष्ट्रकुल देश (सीआईएस) शामिल हैं। इन बाजारों में कंपनी अपने कारोबार के विस्तार और विलय एवं अधिग्रहण के जरिये वृद्धि को रफ्तार जारी रखेगी और

दो वर्षों के दौरान औषधि कंपनियों का प्रदर्शन

अप्रैल से दिसंबर	वित्त वर्ष 20 अनुमान	वित्त वर्ष 20 अनुमान
वित्त वर्ष 19 13.9 अरब डॉलर	वित्त वर्ष 20 15.5 अरब डॉलर	22 अरब डॉलर
तीसरी तिमाही में	वित्त वर्ष 19 डॉलर	वित्त वर्ष 19 19.1 अरब डॉलर
14.6% वृद्धि जबकि दूसरी तिमाही में 8.6% वृद्धि रही थी		

अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 13.9 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। पिछले वित्त वर्ष में कुल औषधि निर्यात 19.1 अरब डॉलर रहा था। औषधि निर्यात के लिहाज से इस साल अब तक के शीर्ष पांच देशों में अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल हैं। भास्कर के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 के शीर्ष पांच निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस और ब्राजील शामिल थे।

पेटेंटयुक्त दवा में दिख रही जबरदस्त वृद्धि

सोहिनी दास

मुंबई, 9 फरवरी

भारत में पेटेंटयुक्त एवं इन–लाइसेंस दवाओं में वृद्धि की जबरदस्त रफ्तार दिख रही है और घरेलू औषधि बाजार में इन दवाओं का योगदान बढ़कर अब 4.5 फीसदी हो चुका है। बाजार अनुसंधान फर्म एआईओसीडी आवाक्स के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पेटेंटयुक्त एवं इन–लाइसेंस दवाओं ने जनवरी 2020 (मैट) में 13.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। मैट का तात्पर्य मूविंग एनुअल टर्नओवर यानी पिछले 12 महीनों के दौरान कुल कारोबार से है। इसके मुकाबले घरेलू औषधि बाजार (पेटेंटयुक्त एवं इन–लाइसेंस दवाओं को छोड़कर) ने समान अवधि में 9.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

बाजार में बिकने वाले शीर्ष ब्रांड पर नजर डालने से भी इसका पता चलता है। डेनमार्क की प्रमुख औषधि कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का इन्सुलिन ब्रांड मिक्सटर्ड पिछली कई तिमाहियों से शीर्ष पायदान पर बनी हुई है। जनवरी के अनुसार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कई ब्रांड भारतीय औषधि बाजार के शीर्ष पांच ब्रांडों की सूची में बरकरार हैं। इनमें सनोफी का इन्सुलिन ब्रांड लैनटस, मर्क की मधुमेह की दवा जैनुमेट और जीएसके की संक्रमणरोधी दवा ऑग्मेनटिन शामिल हैं।

बहुराष्ट्रीय औषधि विनिर्माताओं ने जनवरी में मैट आधार पर 8.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जबकि घरेलू दवा विनिर्माताओं ने इस दौरान 9.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। हालांकि पिछली तिमाही के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वृद्धि दर 6.8 फीसदी पर सुस्त रही जबकि भारतीय कंपनियों के मामले में यह आंकड़ा 11.2 फीसदी रहा।

रोगियों के लिए बढ़ते अनुपालन के साथ पेटेंटयुक्त एवं इन–लाइसेंस दवाओं की मांग में तेजी आई है। इसका मतलब साफ है कि तमाम लोग दवाओं को बीच में ही छोड़ देते हैं लेकिन वे उपचार जारी रखते हैं।



■घरेलू औषधि बाजार में पेटेंटयुक्त एवं इन-लाइसेंस दवाओं का योगदान अब 4.5 फीसदी हो चुका है

■जनवरी में भारतीय औषधि बाजार ने 7.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जिसे मुख्य तौर पर 5.2 फीसदी की कीमत वृद्धि से बल मिला

एक घरेलू कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘औषधि बाजार में मांग कीमत को लेकर लचीला नहीं है। ये जीवन रक्षक दवाएं हैं और लोग इसकी खपत बंद नहीं करते हैं। कुल मिलाकर अनुपालन में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है और इसलिए पेटेंटयुक्त दवाओं को हिस्सेदारी बढ़ी है।’ उन्होंने कहा कि मधुमेह श्रेणी (करीब 14,000 करोड़ रुपये का बाजार) में अधिक मार्जिन वाली अधिकतर दवाएं पेटेंटयुक्त हैं जैसे ग्लिट्पिन और ग्लिफ्लोजिन। जबकि कुछ नवाचारकर्ता यहां उनकी बिक्री खुद करते हैं लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने लाइसेंस का रास्ता भी अपनाया है।

बहरहाल, जनवरी में भारतीय औषधि बाजार ने 7.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जिसे मुख्य तौर पर 5.2 फीसदी की कीमत वृद्धि से बल मिला। लेकिन पिछले 12 महीनों के दौरान मात्रात्मक बिक्री में वृद्धि नकारात्मक (–0.3 फीसदी) रही। एआईओसीडी ने कहा है कि पिछले 12 महीनों के दौरान मात्रात्मक बिक्री में औसत वृद्धि 1.8 फीसदी रही जबकि जनवरी में उल्लेखनीय गिरावट आई।



लाभांश वितरण: बीएसई500 की 60 कंपनियां शेरधारकों को लौटा सकती हैं 88,600 करोड़ रुपये

(टीसीएस) का स्थान है। अन्य दो कंपनियों में प्रमुख एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019 में इन 60 कंपनियों के समेकित कर बाद मुनाफे में सालाना आधार पर 13.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जबकि बीएसई 500 कंपनियों के एकीकृत कर बाद मुनाफे में इस दौरान महज 0.3 फीसदी की वृद्धि हुई।

आईआईएएस ने कहा है, ‘इस सूचकांक में 60 कंपनियों का प्रदर्शन (लाभप्रदता के आधार पर) जबरदस्त रहा जबकि इनमें से लगभग आधी कंपनियों के इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) में एक साल पहले के मुकाबले वित्त वर्ष 2019 के दौरान गिरावट आई। ऐसे में उनके बोर्ड को पूंजी आवंटन की समीक्षा करने के बाद अतिरिक्त रकम शेरधारकों को लौटाना चाहिए।’

आईआईएएस ने 2018 में इसी तरह के एक अध्ययन में उन 92 कंपनियों का संकलन किया

बाजार और भारत है क्योंकि हम इन

बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।’ पिछली कई तिमाहियों के दौरान उभरते बाजारों और भारत में दो अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2019 तिमाही के दौरान कंपनी के कुल राजस्व में उभरते बाजारों का योगदान 20.98 फीसदी और भारत का योगदान 17.4 फीसदी रहा। ऐसे में डॉ रेड्डीज के शीर्ष ने नेतृत्व भविष्य की वृद्धि के लिए अपनी योजनाओं के केंद्र में इन बाजारों को रखा है।

था जो 34,000 करोड़ रुपये अधिक लाभांश का भुगतान कर सकती थीं। अध्ययन के बाद करीब एक दर्जन कंपनियों ने पुनर्खरीद के जरिये अपने शेरधारकों को 37,200 करोड़ रुपये लौटाए जिनमें टीसीएस और इन्फोसिस भी शामिल थीं।

लाभांश पर कर

हालिया बजट प्रस्तावों में लाभांश के संदर्भ में कराधान नियमों में बदलाव किया गया है। कंपनियों के लिए इसे खत्म कर दिया गया है जबकि प्राप्तकर्ताओं/ शेरधारकों के लिए उपयुक्त दर पर इसे लागू किया गया है। यह दर अत्यधिक धनाढ्य शेरधारकों के लिए 43 फीसदी तक हो सकती है।

हालांकि मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषक ऐसा नहीं मानते हैं कि अधिक लाभांश भुगतान के जरिये शेरधारकों को रकम लौटाने के लिए कंपनियों में कोई तत्परता दिखेगी।

मॉर्गन स्टैनली के प्रमुख (इंडिया रिसर्च एवं इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट) रिधम देसाई ने बजट के बाद एक नोट में लिखा, ‘सरकार ने सितंबर 2019 में कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती की थी जिससे कंपनियों को 1.45 लाख करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2020 में डीडीटी के तौर पर करीब 650 अरब रुपये का संग्रह किया जा रहा है। हमारा मानना है कि कंपनियां कर में कटौती के अनुपात में लाभांश में वृद्धि नहीं करेंगी और कर में कटौती का अधिकांश रकम बचा लेंगी। अधिक लाभांश भुगतान करने वाली तमाम कंपनियों की आय में उतनी वृद्धि नहीं दिखेगी जिससे वे अधिक लाभांश को समायोजित कर सकें।’

जल्द होगा उर्वरक नीति में सुधार!

यूरिया के दाम तर्कसंगत किए जाने की संभावना, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को किया जा सकता है हतोत्साहित। सीधे किसानों के खातों में सब्सिडी देने की भी योजना

राजेश भयानी
मुंबई, 9 फरवरी

उर्वरक सुधारों के संबंध में जल्द ही घोषणा हो सकती है। विनिर्माता कंपनियों को मिलने वाले प्रत्यक्ष सब्सिडी लाभ वाली प्रणाली की अपेक्षा किसानों को क्रेडिट देने तथा रासायनिक और जैविक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस बाबत जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने यह जानकारी दी है।

यूरिया के दामों को तर्कसंगत करके या इनसे नियंत्रण हटाकर तथा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए सब्सिडी सीधे किसानों को हस्तांतरित करने के लिए (मौजूदा प्रणाली में कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, इसके बजाय किसानों के खातों में सब्सिडी जमा कराने के लिए) विचार किया जा रहा है।

सूत्र ने बताया कि हालांकि इन उपायों पर पिछले दो महीनों से चर्चा चल रही है, लेकिन वैकल्पिक प्रणाली लागू करना आसान नहीं है और इसीलिए फैसले में देरी हो रही है।

आम बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन में कमी जैसे कुछ उपायों की ओर इशारा किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उर्वरक विभाग की व्यय राशि 71,345 करोड़ रुपये है, जबकि वित्त वर्ष 20 में संशोधित अनुमान करीब 80,000 करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें करीब 11 प्रतिशत की कटौती की गई है।



श्रेणी	वित्त वर्ष 20*	वित्त वर्ष 21**	अंतर (%)
यूरिया			
आयातित	14,049	12,050	-14.2
स्वदेशी	43,050	38,375	-10.9
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	10	10	0.0
फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक			
आयातित	14,429	9,296	-10.9
स्वदेशी	43,050	38,375	-10.9
शहरी खाद	32	29	-9.4
<small>*संशोधित अनुमान, **बजट अनुमान, अंतर सालाना आधार पर</small>			
<small>स्रोत : बजट दस्तावेज, संकलन : वीएस रिसर्च</small>			

फिलिप कैपिटल के संस्थागत शेयर अनुसंधान द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार यह कटौती प्रमुख रूप से कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में

तीव्र बदलाव के अनुरूप है। दरअसल हाल के महीनों में पीएॅंडके (फॉस्फेटिक और पोटैशिक) उर्वरकों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई

है जिससे सब्सिडी के बोझ में राहत मिली है। हालांकि इस क्षेत्र की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए यूरिया की सब्सिडी में कटौती हैरानी की बात है, लेकिन यह आगे चलकर यूरिया की कीमतों को तर्कसंगत बनाते हुए उर्वरकों के संतुलित उपयोग की दिशा में सरकार के कदम बढ़ाने का संकेत हो सकता है।

अगर सब्सिडी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करनी हो, तो यूरिया की कीमतों से नियंत्रण हटाना या इन्हें तर्कसंगत बनाना होगा। हालांकि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण राजकोषीय मसला है, लेकिन जिस तरह का उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है, वह मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है।

उर्वरक नीति को लेकर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने जोर दिया है कि एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम) उर्वरकों के अनुपात पर ध्यान देने के बजाय, जैविक और रासायनिक उर्वरकों के बीच संतुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैविक उर्वरक का जितना अधिक उपयोग होता है, वह मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर रहता है।

जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों के प्रोत्साहन कार्यक्रम की भी संभावना है। हालांकि उद्योग के एक विश्लेषक ने कहा कि जैविक उर्वरकों की उपलब्धता एक समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जैविक उर्वरकों में पोषक तत्व की मात्रा यूरिया की तुलना में कम होती है और इसी वजह से इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है।

कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा रहे प्रवर्तक

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 9 फरवरी

मांग में सुधार और बेहतर लाभ मार्जिन की उम्मीद से कई कपड़ा कंपनियों के प्रवर्तकों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान खुले बाजार में नए शेयरों की खरीद करते हुए अपनी हिस्सेदारी में इजाफा किया है। अप्रैल से दिसंबर 2019 के बीच रेमंड के प्रवर्तकों ने अपनी हिस्सेदारी 290 आधार अंक तक बढ़ाकर 46.7 प्रतिशत कर दी है। इसी तरह अरविंद के प्रवर्तकों ने इस अवधि के दौरान अपनी हिस्सेदारी में 165 आधार अंक तक की बढ़ोतरी की है। कम बाजार पूंजीकरण वाली इंडो रामा सिंथेटिक्स के प्रवर्तकों ने अपनी हिस्सेदारी में 18 प्रतिशत अंक से ज्यादा का इजाफा किया है। फिलाटेक्स इंडिया और ट्राइडेंट जैसी दूसरी कंपनियों ने भी अप्रैल 2019 के बाद से अपनी हिस्सेदारी में इजाफा किया है।

फिलाटेक्स इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मधुसूदन भगेरिया ने कहा कि हमने हाल ही में अपने दहेज संयंत्र में विस्तार संपन्न किया है और

कपड़ा उद्योग



■**पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान पॉलिएस्टर धागे और कपड़े में बढ़ी भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता**

■**अगली एक-दो तिमाहियों के दौरान अवधारणा में सुधार और घरेलू कपड़ा उपभोग तथा निर्यात बढ़ने की उम्मीद**

अप्रैल 2020 तक अतिरिक्त ड्रॉन टेक्सचर्ड यार्न क्षमता वाले संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन शुरू करेंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में पॉलिएस्टर धागे की मांग बढ़ रही

है जिसने हमें अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया है।

पिछली कुछेक तिमाहियों के दौरान भारत पॉलिएस्टर धागे और कपड़े के कारोबार में प्रतिस्पर्धी बन गया है। इसने इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों – अरविंद और फिलाटेक्स को क्रमशः अपनी कपड़ा और पॉलिएस्टर धागा क्षमता में विस्तार के लिए प्रेरित किया है।

एक विश्लेषक ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से फिलहाल पूरी अवधारण कमजोर है। लेकिन हमें अगली एक या दो तिमाहियों के दौरान अवधारणा में सुधार और घरेलू कपड़ा उपभोग तथा निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। वैश्विक कपड़ा निर्यात बाजार में चीन की हिस्सेदारी में गिरावट का लाभ उठाने के लिए सरकार उद्योग के लिए हरसंभव मौका उपलब्ध करा रही है।

प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में इजाफे को सकारात्मक रूप से माना जाता है क्योंकि इससे यह संदेश मिलता है कि प्रवर्तक मौजूदा स्तर पर अपनी कंपनियों में उपयोगिता देख रहे हैं और दीर्घकालिक परिदृश्य को लेकर आशावादी हैं।

प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई में इजाफा

देश के प्रमुख 12 प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान 1.14 प्रतिशत बढ़कर 5,857.2 लाख टन पर पहुंच गई। भारतीय बंदरगाह संगठन (आईपीए) ने इसकी जानकारी दी। इन बंदरगाहों ने पिछले साल की समान अवधि में 5,791 लाख टन माल ढुलाई की थी। इन प्रमुख 12 बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मुरगांव, न्यू मंगलूर, कोचीन, चेन्नई, कामराजर (पूर्ववर्ती एन्नोर), वीओ चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया समेत) शामिल हैं।

आईपीए के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान लौह अयस्क की ढुलाई 39.02 प्रतिशत बढ़कर 450.5 लाख टन पर पहुंच गई। हालांकि कोयले की ढुलाई 14.98 प्रतिशत घटकर 746 लाख टन पर आ गई। साल भर पहले की समान अवधि में

इन 12 बंदरगाहों ने 323.7 लाख टन लौह अयस्क और 877.4 लाख टन कोयले की ढुलाई की थी। कोकिंग कोल एवं अन्य कोयले की ढुलाई 1.10 प्रतिशत बढ़कर 470.8 लाख टन पर पहुंच गई। साल भर पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 465.7 लाख टन रहा था। तैयार उर्वरकों की ढुलाई 21.55 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अपरिष्कृत उर्वरक की ढुलाई में 2.80 प्रतिशत की तेजी आई। इस दौरान कंटेनरों की ढुलाई 2.65 प्रतिशत बढ़ी। आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान दीनदयाल बंदरगाह ने सर्वाधिक 1,019.6 लाख टन की ढुलाई की। इसके बाद पारादीप ने 933.8 लाख टन, विशाखापत्तनम ने 607.3 लाख टन, जेएनपीटी ने 566.4 लाख टन, हल्दिया समेत कोलकाता ने 530 लाख टन, मुंबई ने 513.4 लाख टन, चेन्नई ने 398 लाख टन और न्यू मंगलूर ने 309.1 लाख टन माल की ढुलाई की।

थाया

दार्जिलिंग चाय में सुधार के आसार

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 9 फरवरी

गुणवत्ता गिरने और प्रमुख निर्यात बाजार गंवाने के कारण दामों के कमजोर पड़ने के दो साल से भी ज्यादा समय के बाद इस साल दार्जिलिंग चाय में सुधार आने वाला है। अलग राज्य के लिए गोरखालैंड आंदोलन के बाद वर्ष 2017 में दार्जिलिंग चाय उद्योग मुख्य सीजन के दौरान पूरी तरह ठप पड़ गया था और बिनाई चक्र में अस्थिरता आ गई थी। चाय की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बिनाई जरूरी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गुणवत्ता की वजह से ही दार्जिलिंग चाय, जिसे आम तौर पर ‘चाय की शैम्पेन’ कहा जाता है, के दाम वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक रहते हैं।

दार्जिलिंग चाय संघ (डीटीए) के महासचिव कौशिक बसु ने कहा कि जैसे ही बिनाई चक्र बिगड़ा, इसके साथ ही गुणवत्ता और उत्पादन भी बिगड़ गया। इसके

परिणामस्वरूप गुणवत्ता को नुकसान हुआ जिससे दाम बुरी तरह प्रभावित होते रहे और फिलहाल दाम 20 से 25 प्रतिशत तक कम हैं। हालांकि इस साल हमें दामों में मजबूती आने की उम्मीद है।

आम तौर पर किसी बागान की कुल झाड़ियों के एक-तिहाई भाग में हर साल बिनाई होती है। हालांकि वर्ष 2017 में बंद वापस लिए जाने के बाद कुछ बागान ने पूरी झाड़ियों की बिनाई करने का विकल्प चुना था, जबकि अन्य बागान ने 50

प्रतिशत झाड़ियों की ही बिनाई की थी। कुछ अन्य बागान तो अपनी झाड़ियों की एक-तिहाई बिनाई भी नहीं कर पाए। इससे न केवल बिनाई चक्र बिगड़ा, बल्कि पूरी

गुणवत्ता भी बिगड़ गई और कारोबार में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया। एक बड़ी बात यह रही कि आंदोलन के बाद से इस इलाके में श्रमिकों की बहुत कमी आ गई।

गुडरिक ग्रुप के प्रबंध निदेशक अतुल अस्थाना ने कहा कि बहुत-से श्रमिक अन्य राज्यों में चले गए या दूसरे कामों में लग गए जिससे श्रमिकों की कमी हो गई है। कुछ बागान पर इसका असर पड़ रहा है।

इस संकट की वजह से कुछ

बड़ी कंपनियों ने अपने बागान जैविक बागान में तब्दील कर लिए। इनके लिए उतने श्रम की जरूरत नहीं होती, जितने अजैविक बागान के लिए जरूरत होती है। दार्जिलिंग के 87 बागान में से 70 प्रतिशत फिलहाल जैविक हैं। बसु ने कहा कि वर्ष 2017 में सामान्य फसल चक्र के व्यवधान से दीर्घकालिक असर पड़ा है। वर्ष 2020 में इसके सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जब गुणवत्ता में सुधार होगा, तो दाम भी अच्छे होंगे।

हालांकि भारतीय चाय बोर्ड के आधिकारिक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन डीटीए का अनुमान है कि पिछले साल कुल उत्पादन करीब 80 लाख किलोग्राम रहा। अलबत्ता दार्जिलिंग चाय निर्यात 10 से 12 प्रतिशत तक और दाम 20 से 25 प्रतिशत तक कम रहे हैं।

भारत के कर और खर्च में भारी अंतर

कृष्णकांत और सचिन मामबटा मुंबई, 9 फरवरी

भारत को मिलने वाले कुल राजस्व और उसके व्यय के बीच अंतर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 7.5 प्रतिशत हो गया है। यह अंतर विश्व के बड़े उभरते देशों में सबसे ज्यादा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान के मुताबिक पिछले कैलेंडर वर्ष में सरकार का कुल व्यय जीडीपी के करीब 27.1 प्रतिशत है, जबकि

सरकार का कुल राजस्व जीडीपी का करीब 19.6 प्रतिशत है। भारत में राजस्व और व्यय का अंतर ब्राजील के बराबर ही है, लेकिन यह चीन, रूस और इंडोनेशिया की तुलना में बहुत ज्यादा है।

चीन में पिछले साल सरकार का खर्च कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जीडीपी के 6.1 प्रतिशत से ऊपर था, जबकि रूस में यह जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर कम और इंडोनेशिया में 1.9 प्रतिशत ऊपर था।

सामान्य सरकारी परिचालन के आंकड़ों में राज्य सरकारों को शामिल किया जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन (जैसे नगर

निकाय), राज्य और केंद्र की सरकारी कंपनियों के साथ सामाजिक सुरक्षा कोष इससे बाहर होता है।

अगर एशिया की स्थिति देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जहां सरकार के राजस्व और व्यय में भारी अंतर है। कैलेंडर वर्ष 2019 में पाकिस्तान की सरकार का कमाई की तुलना में खर्च उसके जीडीपी के 8.8 प्रतिशत से ज्यादा था। इसकी तुलना में बांग्लादेश में यह अंतर महज 4.8 प्रतिशत, श्रीलंका में 5.7 प्रतिशत और वियतनाम में 4.4 प्रतिशत था।

भारत में तुलनात्मक रूप से ज्यादा राजकोषीय अंतर देश के सरकारी कर्ज और जीडीपी के अनुपात के बढ़ने के रूप में सामने आता है। आईएमएफ ने भारत पर अपने हाल के परामर्श पत्र में कहा है, ‘वित्त वर्ष 20 में भारत का सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का करीब 69 प्रतिशत है, जो अन्य बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत ज्यादा है।’

सार्वजनिक कर्ज ज्यादा बढ़ने की प्रमुख वजह आईएमएफ ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को बताया है। आईएमएफ ने कहा, ‘ऑफसेटिंग के कदम न होने के कारण कर कटौती के बाद सरकार



का कर्ज वित्त वर्ष 2020 में 10 साल के उच्च स्तर, जीडीपी के 69 प्रतिशत पर पहुंच गया है।’

ज्यादा सार्वजनिक कर्ज होने से सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता है, जो वित्त वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी का 4.9 प्रतिशत था, जो उभरते बड़े बाजारों की तुलना में बहुत ज्यादा है।

आईएमएफ के मुताबिक अन्य 4 ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका में यह अनुपात करीब 3 प्रतिशत है, जबकि आसियान देशों में यह करीब 1.5 प्रतिशत है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की तुलना

■ विश्व के उभरते बाजारों की तुलना में भारत का राजकोषीय अंतर सबसे ज्यादा

■ केंद्र व राज्य सरकारों का संयुक्त खर्च 2019 में राजस्व की तुलना में जीडीपी के 7.5 प्रतिशत के करीब ज्यादा

■ वैश्विक कारोबारी चुनौतियों व आयात में वृद्धि कम होने की वजह से केंद्र सरकार का कर आधार भी सिकुड़ा

मुख्य निवेश अधिकारी पीयूष गर्ग ने कहा कि अगर कर्ज व जीडीपी का अनुपात बढ़ता रहेगा तो सरकार की उधारी लेने की क्षमता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा, ‘भारत का कुल मिलाकर कर्ज जीडीपी का अनुपात उभरते बाजारों की तुलना में अलग है।’

उन्होंने कहा कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि भी सुस्त रही है, जिसकी वजह से यह राशि सीमित होती है और इसके कारण घाटा बढ़ सकता है। ज्यादा कर्ज का जोखिम भारत को कई तरीके से प्रभावित कर सकता है, जिसमें मुद्रा नीचे जाने का दबाव शामिल है।

हुई है।’ उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति कुछ समय तक और बनी रह सकती है।

ज्यादा घाटे के आंकड़े सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उभरते अगड़े देशों में भी यह बढ़ेगा। ऐसा सलाहकार फर्म ने जनवरी 2020 को इकनाॉमी वाच रिपोर्ट में कहा है।

अमेरिका का राजकोषीय घाटा और जीडीपी का अनुपात 2019 में बढ़कर 7 प्रतिशत रह सकता है और यह बढ़ा हुआ बना रहेगा। ब्रिटेन में भी यह अंतर बढ़ रहा है। चीन और दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। ईवाई इंडिया के प्रमुख नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने लिखा है कि भारत में राजस्व को लेकर उसकी जीडीपी के लेकर उसकी तुलना में भी मदद मिल सकती है।

केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है, ‘पिछले कुछ साल से आर्थिक मंदी की स्थिति है, जिसकी वजह से सरकार को वृद्धि को बल देने के लिए ज्यादा धन खर्च करना पड़ा है। इसका यह भी मतलब है कि वह राजकोषीय घाटे के पहले के लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं रही है। कम वृद्धि दर की वजह से कर संग्रह भी कम रहा है, जिसकी वजह से स्थिति और गंभीर

गर्ग का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में इसमें सुधार की कुछ उम्मीद है। इससे सकार के वित्त को भी मदद मिल सकती है। केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है, ‘पिछले कुछ साल से आर्थिक मंदी की स्थिति है, जिसकी वजह से सरकार को वृद्धि को बल देने के लिए ज्यादा धन खर्च करना पड़ा है। इसका यह भी मतलब है कि वह राजकोषीय घाटे के पहले के लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं रही है। कम वृद्धि दर की वजह से कर संग्रह भी कम रहा है, जिसकी वजह से स्थिति और गंभीर

संक्षेप में

आयातकों-निर्यातकों को देनी होगी पहचान संख्या

आयातकों और निर्यातकों को 15 फरवरी से दस्तावेजों में अनिवार्य तौर पर वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) की जानकारी उपलब्ध करागी होगी। राजस्व विभाग जीएसटी से राजस्व संग्रह में हो रहे नुकसान को रोकने तथा कर चोरी पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया है।

भाषा

निर्यातकों से जिला स्तर के आंकड़े मांगे

निर्यातकों को अब निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की अतिरिक्त सूचना देनी होगी। उन्हें सीमा शुल्क विभाग से संबंधित उत्पाद के मूल जिले का उल्लेख करना होगा। यह व्यवस्था 15 फरवरी से लागू होने जा रही है। इससे सरकार निर्यात को प्रोत्साहन के लिए अपनी नीतियों को बेहतर कर सकेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सकुलर के अनुसार निर्यातकों को अब वस्तु के मूल स्रोत, संबंधित उत्पाद का निर्यात किस तर्जोही समझौते के तहत किया जा रहा है, उसका ब्योग और मानक इकाई मात्रा संहिता की जानकारी देनी होगी।

भाषा

अगले 3 साल बनी रहेगी 4 हवाईअड्डों पर भीड़

चार बड़े शहरों में स्थित हवाईअड्डों पर क्षमता विस्तार की 38 हजार करोड़ रुपए की चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण कम से कम 2023 तक इन हवाईअड्डों पर यात्रियों की लम्बी घुमावदार कतारें देखने को मिल सकती हैं। एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाईअड्डों से आधे से अधिक आवागमन होता है और ये हवाईअड्डे अपनी क्षमता का 130 प्रतिशत परिचालन कर रहे हैं। इनकी क्षमता विस्तार का काम 2023 के अंत से पहले पूरा होने का अनुमान नहीं है।

भाषा

470 करोड़ रुपये की टीडीएस चूक पकड़ी गई

आयकर विभाग ने दिल्ली की कई बड़ी कंपनियों द्वारा 470 करोड़ रुपये की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की चूक का मामला पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि हाल में इन कंपनियों पर छापेमारी के बाद मामला सामने आया है।

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

जीएसटी दरें साल में एक ही बार बदलें

नम्रता आचार्य

कोलकाता, 9 फरवरी

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा



उन्होंने कहा, ‘हम उद्योग से बार

बार कह रहे हैं... जब भी वह हमसे दरें कम करने को लेकर संपर्क करते हैं... वे अपनी चिंता राज्यों के समक्ष भी रखें और राज्य के मंत्री भी जीएसटी परिषद में इस तरह की चिंता सामने रखें। यह संघीय ढांचा है, जहां केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध है।’

करदाताओं के कर भुगतान के विकल्प पर सीतारमण ने संकेत दिए कि जो लोग दीर्घावधि निवेश करेंगे, वह

उन्होंने कहा, ‘हम उद्योग से बार

बार कह रहे हैं... जब भी वह हमसे दरें

कम करने को लेकर संपर्क करते हैं...

वे अपनी चिंता राज्यों के समक्ष भी रखें

और राज्य के मंत्री भी जीएसटी परिषद

में इस तरह की चिंता सामने रखें। यह

संघीय ढांचा है, जहां केंद्र और राज्य के

बीच बेहतर संबंध है।’

करदाताओं के कर भुगतान के

विकल्प पर सीतारमण ने संकेत दिए कि

जो लोग दीर्घावधि निवेश करेंगे, वह

उन्होंने कहा, ‘हम उद्योग से बार

बार कह रहे हैं... जब भी वह हमसे दरें

कम करने को लेकर संपर्क करते हैं...

वे अपनी चिंता राज्यों के समक्ष भी रखें

और राज्य के मंत्री भी जीएसटी परिषद

में इस तरह की चिंता सामने रखें। यह

संघीय ढांचा है, जहां केंद्र और राज्य के

बीच बेहतर संबंध है।’

करदाताओं के कर भुगतान के

विकल्प पर सीतारमण ने संकेत दिए कि

जो लोग दीर्घावधि निवेश करेंगे, वह

उन्होंने कहा, ‘हम उद्योग से बार

बार कह रहे हैं... जब भी वह हमसे दरें

कम करने को लेकर संपर्क करते हैं...

वे अपनी चिंता राज्यों के समक्ष भी रखें

और राज्य के मंत्री भी जीएसटी परिषद

में इस तरह की चिंता सामने रखें। यह

संघीय ढांचा है, जहां केंद्र और राज्य के

बीच बेहतर संबंध है।’

करदाताओं के कर भुगतान के

विकल्प पर सीतारमण ने संकेत दिए कि

जो लोग दीर्घावधि निवेश करेंगे, वह

उन्होंने कहा, ‘हम उद्योग से बार

बार कह रहे हैं... जब भी वह हमसे दरें

कम करने को लेकर संपर्क करते हैं...

वे अपनी चिंता राज्यों के समक्ष भी रखें

और राज्य के मंत्री भी जीएसटी परिषद

में इस तरह की चिंता सामने रखें। यह

संघीय ढांचा है, जहां केंद्र और राज्य के

बीच बेहतर संबंध है।’

करदाताओं के कर भुगतान के

विकल्प पर सीतारमण ने संकेत दिए कि

समाधान करना होता है। मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में अलग हैं और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।’

साथ ही दो कर व्यवस्था में

करदाताओं को निवेश के व्यापक

विकल्प होंगे, जिसमें शेयर बाजार और

बॉन्ड मार्केट के डेट इंस्ट्रुमेंट में निवेश

शामिल है, जहां मुनाफा बचत के

परंपरागत निवेश विकल्पों की तुलना में

बराबर या उससे ज्यादा है।

सीतारमण ने कहा, ‘जिन लोगों को

लगता है कि वे छूट के माध्यम से ही

बचत कर सकते हैं, वे पुरानी व्यवस्था

जारी रख सकते हैं। जिन्हें लगता है कि

वे अपने धन के बारे में उचित फैसला

लेने में सक्षम हैं, उनके हाथ में नई

प्रणाली से ज्यादा पैसे आएं और उन्हें

अपनी आमदनी अपनी इच्छा के

मुताबिक निवेश में लगाने की आजादी

होगी। कोई जरूरी नहीं है कि बैंक में

जमा या डाकघर जमा या सावधि जमा

से ही बचत हो। अब बचत शेयर बाजार

में जा सकती है या बॉन्ड बाजार में उसे

डेट में निवेश किया जा सकता है, जिसके

मुनाफा पहले के निवेशों के बराबर या

उसकी तुलना में ज्यादा है।’

बढ़ेगा बोझ

■ एलआरएस के तहत 5 प्रतिशत

कर लगाए जाने का असर उन

विद्यार्थियों पर पड़ना तय

■ विशेषज्ञों के मुताबिक यह कर

प्रेषण की पूरी कवायद को जटिल

बना देगा

■ भारतीयों ने वित्त वर्ष 2019 में

11.34 अरब डॉलर एलआरएस

के तहत विदेश में भेजे

■ सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी

मोदी ने कहा कि यह प्रेषण की

सूची बनाने और उससे रिटर्न से

मिलान करने का मामला

11.34 अरब डॉलर एलआरएस के

तहत विदेश में भेजा था, जिसमें

करीब 3.5 अरब डॉलर विदेश में

शिक्षा के मकसद से भेजा गया।

एक कर विशेषज्ञ ने कहा,

‘अगर विदेश भेजी गई राशि

प्रेषक ने पहले ही आयकर का

भुगतान कर दिया है तो इससे तब

तक ग्राहक का धन सरकार के पास

फंसा रहेगा, जब तक कि वह रिफंड

जम्मू कश्मीर को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की भांति मिलेगा कर में हिस्सा

इंद्रविजल धम्मना और अरूप रायचौधरी नई दिल्ली, 9 फरवरी

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

भाषा

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 305

कोरोनावायरस का असर

सन 2003 में सीवियर एक्टूट रेस्पिरटरी सिंड्रोम (सार्स) बीमारी के फैलने से पूर्वी एशिया में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और इसने विश्व अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। हालांकि उस प्रभाव से निपटने में कामयाबी मिली थी। सार्स बीमारी चीन में उभरी और उसकी वृद्धि को इसकी कोमल चुकानी पड़ी। परंतु उस वक्त

अर्थव्यवस्था की गति इतनी तेज थी कि वह जल्दी ही इसके प्रभाव से उबरने में कामयाब रही और रिकॉर्ड गति से बढ़ती रही। आज जब चीन के ही वुहान शहर में कोरोनावायरस जैसी आपदा उभरी है तो हालात अलग हैं। चीन 2003 की तुलना में आज विश्व आपूर्ति शृंखला से कहीं अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। उस वक्त वैश्विक उत्पादन का केवल 5

प्रतिशत चीन से आता था। इतना ही नहीं आज चीन की अर्थव्यवस्था भी पहले जितनी मजबूत नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोनावायरस सार्स से अधिक खतरनाक है। चीन की प्रतिक्रिया ढीली रही लेकिन आखिरकार वह संकट से निपटने के सघन प्रयास कर रहा है। वैश्विक नेटवर्क वाली कई फैक्ट्रियां वहां अपना काम अस्थायी रूप से बंद कर रही हैं। कुछ उद्योगों पर इसका असर देखने को मिलेगा, मसलन वाहन और मोबाइल फोन उद्योग। ये दोनों उद्योग चीन की फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन पर काफी हद तक निर्भर हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोनावायरस से जुड़ा सबसे बुरा परिदृश्य अभी भी सामने आना बाकी है। निश्चित तौर

पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक इसे महामारी का दर्जा नहीं देकर सावधानी बरती है लेकिन इसका असर जल्दी देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए भारतीय वाहन उद्योग के पास चीन से आने वाले कलपुर्जों की बमुश्किल कुछ सप्ताह की आपूर्ति बची है। औषधि उद्योग जो देश की आय का बड़ा स्रोत है वह देश के लिए अच्छी खासी निर्यात आय अर्जित करता है। वह औषधियों के कई जरूरी तत्व चीन से आयात करता है। कई बार तो यह आयात 80 प्रतिशत तक होता है। जाहिर है भारत पर कोरोनावायरस का आर्थिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। माना जा रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में कोरोनावायरस बहुत प्रभावी नहीं होगा। भारत में पहला मामला कुछ समय पहले केरल में

सामने आया। बहरहाल, अभी यह निश्चित नहीं है कि केवल केरल के मामले ही चिंता का विषय हैं। आखिरकार भारतीय जन स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया की सबसे प्रभावी व्यवस्थाओं में से नहीं है। चिंता की बात है लेकिन यह संभव है कि कुछ मामले इन कमियों के बीच देश में आ गए हों। अभी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि कोरोनावायरस के वैश्विक मामले नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। परंतु सरकार को इस बारे में स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए कि अगर देश में इस बीमारी के मामले बढ़ते हैं तो क्या कदम उठाए जाएंगे। एक महामारी से निपटने के लिए कम समय में क्षमता निर्माण कैसे किया जाए?

सरकार को कोरोनावायरस के प्रभावों से

निपटने के अन्य तरीकों की भी तैयारी रखनी होगी। ऐसा असर कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में नजर आने लगा है। इस बाजार में अब मंदी आ गई है। ब्रेंट क्रूड की अप्रैल आपूर्ति अब 55 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार रहा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में प्रति दिन 200,000 बैरल की कमी आ सकती है। यदि बड़े तेल उत्पादक देश उत्पादन कम नहीं करते तो तेल कीमतों में काफी गिरावट आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय राजकोष और बाह्य खाते के मोर्चे पर काफी सहजता आएगी। सन 2014 और 2015 में जब तेजी कीमतों में निरंतर गिरावट आने लगी थी तो ऐसा ही हुआ था। सरकार को इसका फायदा उठाते हुए अपनी वित्तीय स्थिति दुरुस्त करनी चाहिए।



अजय मोहंती

नेहरू पर शाब्दिक प्रहार की क्या है वजह!

मोदी नेहरू पर निरंतर हमला कर सकते हैं। एक भाषण में 23 बार भी। इसलिए नहीं कि वह कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनके अनुसार स्वतंत्र भारत की दोषपूर्ण कल्पना पर नेहरू की छाया है

नरेंद्र मोदी क्या किसी अजीब मनोविकार के शिकार हैं जिसे नेहरूआइटिस का नाम दिया जा सकता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में उन्होंने जो 100 मिनट का भाषण दिया उसमें नेहरू का नाम 23 बार लिया। तो क्या सचमुच वह किसी बीमारी के शिकार हैं? वह पुरानी स्वस्थ संसदीय बहस परंपरा का पालन करते हुए कांग्रेस के नेताओं के साथ चुलल करते हैं लेकिन राहुल गांधी के प्रति उनका रवैया तिरस्कार का ही रहता है। वह उनका नाम तक नहीं लेते या कहे इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं।

यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर न है तो फिर वह क्यों से ऐसा क्यों करते आ रहे हैं? जब भी मोदी के अधीन किसी काम में गड़बड़ी होती है तो सोशल मीडिया पर उनके तमाम आलोचक तत्काल मखौल उड़ते हुए कहते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, मोदी को मुझे सहारा देना जा सकता। मोदी के सभी वक्तव्यों को याद कीजिए, वह यूं ही दिए गए हों, चुनाव प्रचार की गरमागरमी में दिए गए हों या संसद में। नेहरू का जिक्र बार-बार आता है। ताजा भाषण में 23 बार उनका जिक्र आने से लोगों का ध्यान उस पर गया लेकिन वर्ष 2014 के बाद से अगर मोदी ने हर वर्ष सैकड़ों बार नेहरू का नाम न लिया हो तो मुझे आश्चर्य होगा।

उन्होंने तो 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी नेहरू को घसीट लिया था। उस समय मोदी ने आरोप लगाया था कि नेहरू ने प्रतिष्ठित सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिम्मा (1957-61) का अपमान किया था। थिम्मा कर्नाटक के रहने वाले थे। जब आप मोदी को ताना मारते हुए कहते हैं कि अमुक काम में नेहरू की गलती थी, वह इसका बुरा नहीं मानते। शायद उन्हें भी इस पर यकीन है। भारत के साथ जो भी गलत हुआ और हो रहा है, यानी कश्मीर से लेकर चीन तक और सरकारी कंपनियों से लेकर बेरोजगारी

तक, उनकी नजर में सब नेहरू की गलती है। मोदी-शाह की भाजपा का विश्लेषण करते हुए हम पुरानी शैली के विश्लेषक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम पुराने और जाने-पहचाने संदर्भों का प्रयोग करते हैं या कहे कसीटी का इस्तेमाल करते हैं। मोदी-शाह की भाजपा कोई अनूठी पार्टी नहीं है। आप इसे भाजपा, जनसंघ, आरएसएस कुछ भी कहें यह एक हकीकत है। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के अधीन हमें अपवाद देखने को मिला। भारतीय राजनीति पर नजर रखने वाले हम पुराने लोगों की तरह वे भी पुरानी ढब के लोग थे। वाजपेयी इसे समावेशी और उदारवाद कहते। मोदी और शाह की जवान में इसे नेहरूवाद कहा जाता।

आरएसएस में बहुत गहरी मान्यता है कि नेहरू सन 1947 में देश का नेतृत्व हासिल करने के काबिल नहीं थे। उन्होंने गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन को बहकाया और सरदार वल्लभभाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और एक बार सत्ता हथियाने के बाद उन्होंने अपने नजरिये वाला गणतंत्र बनाना शुरू किया। उन्होंने अफगान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जगह सम्राट अशोक और बुद्ध की शांतिप्रियता को शासन के प्रतीक के रूप में चुना।

लंबोलीआब यह कि नेहरू ने चतुर्गुणपूर्ण ढंग से नए भारत को गैर-हिंदू छवि में ढाला। इससे तमाम दिक्कतें पैदा हुईं। अल्पसंख्यकों के तुट्टीकरण से लेकर सेना की अनदेखी, परिचामी विचारों, आर्थिक मॉडल की दासता जैसी बातें इसका उदाहरण हैं। पूरा नेहरूवादी बौद्धिक परिवेश उनके इर्दगिर्द ही बना और सात दशक तक देश की विचार प्रक्रिया पर काबिज रहा। मोदी और शाह तथा उनकी



राष्ट्र की बात शेखर गुप्ता

पीढ़ी के भाजपा नेताओं के लिए जो आमतौर पर गैर अंग्रेजीभाषी और गैर पश्चिमी माहौल से उभरे हैं, उनके लिए यह उभरने का विषय है। इसी कारण मोदी जब एक भाषण में 23 बार नेहरू का जिक्र करते हैं तो यह उनके दिल से निकली बात है। मोदी के लिए यह नेहरू पर ध्यान केंद्रित करने का उपयुक्त समय है।

वह राहुल से सीधे कभी नहीं उलझते। उन्हें नाम लेने लायक भी नहीं समझते लेकिन उनकी पार्टी के अन्य नेताओं से जरूर संपर्क करते हैं। अधीर रंजन चौधरी से मित्रवत चुटकी लेना हो या शशि थरूर पर फन्की कसना, गुलाम नबी आजाद की तारीफ या दिग्विजय सिंह से कविता कहने की होड़ लगाने तक इसके तमाम उदाहरण हैं। यहां तक कि उन्होंने मनमोहन सिंह को महान व्यक्तित्व और विद्वान बताते हुए उनकी सरहना की। तीसरा, वह नेहरू के समकालीन और आलोचक राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं की भी तारीफ करते हैं। हमारे लिए चौथे सवाल का उत्तर यहीं है। सवाल यह कि आखिर मोदी नेहरू-गांधी परिवार के सारे नेताओं में केवल नेहरू पर हमला क्यों करते हैं? एक स्तर पर यह विशुद्ध राजनीति है। वह मानते हैं कि कांग्रेस वंशवाद पर टिकी है जो काफी हद तक नेहरूवादी देन है। यदि वह उसे हटा सकें तो गांधी परिवार का परभाव है। साथ ही उस विचार और पार्टी का भी। अन्य नेताओं, छोटे विपक्षी दलों आदि से वह आसानी से निपट सकते हैं। इस प्रक्रिया में वह अपने और अपने उत्तराधिकारियों के लिए ऐसी जगह भी बना लेंगे जहां भारत को आरएसएस के विचार में ढाला जा सके। नेहरू के भ्रमित अशोकवादी शासन की जगह कौटिल्य के कबरे में हम यह जानते हैं कि वे पूरी तरह

भावनाओं से संचालित नहीं होते, न ही वे बौद्धिक और राजनीतिक आनंद के लिए पुरानी बहसों को जिंदा करने में वक्त जाया करते हैं। यहां चौथा सवाल पैदा होता है जिसका जिक्र तो हमने किया था लेकिन व्यापक राजनीतिक बहस दूर न हो जाए इसलिए उस पर विस्तार से बात नहीं की। सन 2014 के बाद मोदी के राजनीतिक संदेशों में तीन और बातें निरंतर हैं। पहली बात, वह कभी नेहरू-गांधी परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला नहीं करते। वह राजीव गांधी का जिक्र करना जरूरी नहीं समझते। उन्होंने कभी इंदिरा गांधी पर हमला नहीं किया। वह आपातकाल का जिक्र करते हैं लेकिन इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेते।

इसके पीछे की राजनीति समझना मुश्किल नहीं है। नेहरू-गांधी परिवार के सभी सदस्यों में आज भी इंदिरा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इसे इस बात से समझिए कि उनके पुराने 1, सफदरजंग रोड स्थित आवास पर जिसे उनकी हत्या के बाद स्मारक में बदल दिया गया, वहां आज भी देश भर से बड़ी तादाद में लोग आते हैं, खासतौर पर दक्षिण भारत से बसों में भरकर। दूसरी बात पर मैं अटकल लगा रहा हूँ और वह यह कि मोदी शायद गुप्त रूप से उनके प्रशंसक भी हैं। शायद इसलिए कि उन्होंने पार्टी और सरकार पर जरूरतस्व नियंत्रण रखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें व्यापक प्रतिष्ठा हासिल है और उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। शायद यही कारण है कि वह कभी इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं करते।

दूसरी बात, आप देखेंगे कि मोदी पटेल के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं को निरंतर तारीफ करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को तो आरएसएस ने काफी हद तक अपने प्रतीक में बदल दिया है। गत गुरुवार के भाषण में भी उनका एक से अधिक बार सकारात्मक तरीके से जिक्र सुनने को मिला।

वह राहुल से सीधे कभी नहीं उलझते। उन्हें नाम लेने लायक भी नहीं समझते लेकिन उनकी पार्टी के अन्य नेताओं से जरूर संपर्क करते हैं। अधीर रंजन चौधरी से मित्रवत चुटकी लेना हो या शशि थरूर पर फन्की कसना, गुलाम नबी आजाद की तारीफ या दिग्विजय सिंह से कविता कहने की होड़ लगाने तक इसके तमाम उदाहरण हैं। यहां तक कि उन्होंने मनमोहन सिंह को महान व्यक्तित्व और विद्वान बताते हुए उनकी सरहना की। तीसरा, वह नेहरू के समकालीन और आलोचक राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं की भी तारीफ करते हैं।

हमारे लिए चौथे सवाल का उत्तर यहीं है। सवाल यह कि आखिर मोदी नेहरू-गांधी परिवार के सारे नेताओं में केवल नेहरू पर हमला क्यों करते हैं? एक स्तर पर यह विशुद्ध राजनीति है। वह मानते हैं कि कांग्रेस वंशवाद पर टिकी है जो काफी हद तक नेहरूवादी देन है। यदि वह उसे हटा सकें तो गांधी परिवार का परभाव है। साथ ही उस विचार और पार्टी का भी। अन्य नेताओं, छोटे विपक्षी दलों आदि से वह आसानी से निपट सकते हैं। इस प्रक्रिया में वह अपने और अपने उत्तराधिकारियों के लिए ऐसी जगह भी बना लेंगे जहां भारत को आरएसएस के विचार में ढाला जा सके। नेहरू के भ्रमित अशोकवादी शासन की जगह कौटिल्य के धार्मिक राज्य की तरह।

सार्वजनिक वक्तव्य के मानक में आती जा रही गिरावट

हाल में तीन दिन के अंतराल में दो महत्वपूर्ण भाषण दिए गए। पहला दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में और दूसरा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में। दोनों भाषण ऐसे वक्त पर दिए गए जब उन देशों में सत्ता प्रतिष्ठान के समक्ष राजनीतिक चुनौतियां उठाने पर हैं। इन दोनों भाषणों को ऐसी वजहों से याद किया जाएगा जो भाषण की विषयवस्तु से इतर हैं। दरअसल दोनों भाषण सार्वजनिक वक्तव्यों के गिरते मानक से ताल्लुक रखते हैं।

पहला भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है जो उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए दिया। खराब होती आर्थिक परिस्थितियों के बीच दिया गया यह भाषण दो घंटे 43 मिनट लंबा था। यदि उनकी तबियत खराब न होती तो यह और लंबा हो सकता था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह भाषण तमाम आकांक्षाओं पर विफल रहा।

उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम स्टेट ऑफ द यूनियन (एसओटीयू) भाषण में 78 मिनट का समय लिया। इस भाषण के दौरान कम से कम 100 बार लोगों की तालियों (केवल रिपब्लिकन) के कारण भाषण रोकना पड़ा और रियलिटी टेलीविजन जैसे दृश्य रचे गए (अफगानिस्तान से एक सैनिक का अचानक अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौटना)। परंतु ट्रंप को पता था कि वह एक राष्ट्रपति के पीछे उनके भाषण की अपनी प्रति फाइंडर महफिल लूट ली। दरअसल ट्रंप ने हाउस स्पीकर नैंसी पेलेसी की हाथ मिलाए की कोशिश की अनदेखी कर दी थी।

सीतारमण को किसी ने अपमानित नहीं किया। भाषण समाप्त होने से पहले जब उनकी तबियत बिगड़ी तो विपक्ष के कई सांसद उनके पास पहुंचे। उन्होंने अपना संदेश देने का हरसंभव प्रयास किया। सुनहरी साड़ी में सजी सीतारमण ने एक कश्मीरी कविता का अंश पढ़ा (जैसा कि मेरी सहयोगी आर्दिती फडणीस ने बताया, उन्होंने कवि का कूट नाम जो उर्दू में था, की अनदेखी



जिंदगीनामा कनिका दत्ता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में स्कूल स्तर की किसी प्रतियोगिता जैसा उतार-चढ़ाव था जो काफी हद तक उबाऊ था। हालांकि करीब तीन घंटों की कवायद के बावजूद आखिरकार आंकड़े अपनी बात खुद कहेंगे

की), उन्होंने प्राचीन तमिल महिला संत कवि की एक कहावत साझा की और एक कुल यानी तमिल पवित्र कथन का उच्चारण किया। उन्होंने भाषण के आखिर में कालिदास का भी जिक्र किया। यह वह हिस्सा था जिसमें कर प्रस्ताव शामिल होते हैं। हर साहित्यिक संदर्भ की व्याख्या की गई, हर प्रस्ताव और उपलब्धि को कम से कम दो बार दोहराया गया। परंतु इस कड़ी मेहनत का नतीजा, इसे अहम बातने की पूरी कोशिश उनके उच्चैत अंकेशकों ने गंवा दी।

वित्त मंत्री के भाषण में स्कूल स्तर की किसी प्रतियोगिता जैसा उतार-चढ़ाव था जो काफी हद तक उबाऊ था। परंतु टेलीविजन ने भी हमें निराश किया। कांग्रेस नदारद थी इसलिए दूरदर्शन के छायाकारों के पास लोगों को दिखाने के लिए सीमित विकल्प थे। वे कैमरे से लॉन्ग शॉट नहीं ले सकते थे, नहीं तो विपक्ष की खाली बेंच नजर आ जातीं। अतीत में बजट के दौरान यह संभव था कि मंत्री के किसानों, गरीबों, महिलाओं, असुसूचित जातियों आदि की मदद की बातों के बीच कुछ राहत पाई जा सके। साड़ी

पहने सोनिया गांधी, बुद्धिमान दिखने की कोशिश करते राहुल गांधी, सुषमा स्वराज के करीने से बनाए हुए बाल आदि। साधू और साध्वी, पगड़ी और हैट। पीछे बैठे उबावियों लेते लोग, लोकसभा अध्यक्ष के मंच के ठीक नीचे अनुवादकों की आपाधापी आदि तमाम बातें थी जो आपका ध्यान बंटता सकती थीं। इस बार सीतारमण की बातों के दोहराव के अलावा अवश्य बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री के भावहीन चेहरे के क्लोजअप शॉट देखने को मिले।

एक घंटा बीतते-बीतते बजट भाषण सुनने वाले हम जैसे लोगों को मुश्किल होने लगी। आर्थिक पत्रकार पूजा मेहरा ने ट्वीट किया कि बजट के कारण कॉफी की खपत अवश्य बढ़ रही है। एक घंटे बाद तो कॉफी भी नाकाम होने लगी। जब बजट के दूसरे खंड यानी पार्ट बी की बारी आई तो आयकर में बदलाव को लेकर मामूली शुरुआती उत्साह के बाद भ्रम की स्थिति बन गई जो अब तक जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि वह सनदी लेखाकार मुक्त कर प्रस्ताव रख रही हैं। जबकि सच तो यह है कि अब उनकी और जरूरत पड़ने वाली है। एक के बाद एक वित्त मंत्रियों ने सरकार की वित्तीय स्थिति की लेकर सालाना रिपोर्ट बनाई है जिसे एसओटीयू के समकक्ष रखा जा सकता है क्योंकि एसओटीयू की तरह इसके श्रोता भी सीमित होते हैं। परंतु एसओटीयू को राजनीतिक प्रगति संबंधी रिपोर्ट माना जाता है जो देश का मुखिया कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करता है। दिलचस्प बात है कि ऐसे हर भाषण में बजट संदेश आवश्यक है।

इस वर्ष अमेरिका के फैंक चेंकर ट्यूथकॉम्ब ने पाया कि ट्रंप के एसओटीयू वक्तव्य में भ्रामक बातें पहले की तुलना में कहीं अधिक थीं। सीतारमण की दिक्कत यह है कि हर बजट में साथ आने वाले कई दस्तावेज लंबे समय तक संकलनों की नजर में रहते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि बजट इतना लंबा था कि वह कुछ भी समझ नहीं पाए (अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व वित्त मंत्री ने बजट के दौरान यह संभव था कि मंत्री के किसानों, गरीबों, महिलाओं, असुसूचित जातियों आदि की मदद की बातों के बीच कुछ राहत पाई जा सके। साड़ी

कानाफूसी

उत्तर दक्षिण का मेल

बजट की शाम बादल परिवार के सालाना मक्की रोटी- सरसों साग के दोपहर भोजन में उत्तर और दक्षिण का जबरदस्त मिलन देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और उनके पति तथा सांसद सुखबीर सिंह की मेजबानी वाले इस भोजन में अमृतसरी कुलचे और मक्की रोटी जैसे पंजाबी पकवानों के बीच दोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन को भी स्थान मिला था। भोजन उन खानसामों ने पकाया था जो अपने साथ पंजाब से पानी तक लेकर आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के पानी में वह बात नहीं है। लेकिन पंजाब के पानी में बने दोसे के बावजूद सारी सुखियां कुलचों, मक्की रोटी, चाट, गरम जलेबी, गुलाब जामुन और गाजर के हलवे ने बटोरें। जहां तक अतिथियों की बात है, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस भोजन का लुत्फ लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर के अलावा सुप्रिया सुले, राजीव शुक्ला, कनिमोई और किरण खेर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान एक नेता की कमी सभी ने महसूस की और वह थे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जिनका गत वर्ष अगस्त में निधन हो गया था।



आपका पक्ष

गांवों में मनरेगा से ही विकास संभव

भारत के कृषि प्रधान देश होने के बावजूद देश में ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी, गांव से शहर की ओर पलायन, मानव तस्करी, निम्न ग्रामीण जीवन स्तर आदि समस्याएं निरंतर विकराल रूप धारण करती जा रही थी। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए मनरेगा की शुरुआत की गई। हालांकि पूर्व में भी दोसे में काम के बदले अनाज तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी योजनाएं सक्रिय थीं। लेकिन अब इन्होंने मनरेगा के अंतर्गत शामिल करके इस महाअभियान को व्यापक रूप देने की पहल की गई है। विश्व में भी केवल भारत ही ऐसा देश है जिसमें रोजगार के लिए एक अधिनियम बनाया जो कानूनी तौर पर रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। मनरेगा ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल प्रदान किया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कहीं खोखली साबित न हो जाए, इसके लिए मजबूत निगरानी तंत्र, ग्रामीणों में जागरूकता प्रसार, मजबूत



राजनीतिक इच्छाशक्ति और उचित क्रियान्वयन समय की मांग है। सरकार ने इस बजट में भी इसके लिए राशि नहीं बढ़ाई है जो गांव के विकास के लिए एक बड़ा झटका है। पहले से ही मनरेगा का कोष कम है, अब इसे राश्यों पर बोझ डाल कर छोड़ दिया गया है। अगर सरकार मनरेगा पर खर्च करती हो यहां मांग बढ़ सकती थी जो गरीबों और

मनरेगा योजना देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है

विकास दर दोनों के लिए बेहतर होता। साथ ही साथ डूबी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने में मदद मिलती।

अनु मिश्रा, सीवान

जागरूक रहें और जागरूकता फैलाएं

कोरोनावायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका इसको लेकर स्वयं जागरूक रहना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। अपने आस पास सफाई बनाए रखना, हाथ को साबुन और सैनिटाइजर से साफ करना, छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना आदि उपाय अन्य वायरस जनित बीमारियों की तरह ही इससे भी बचाव का उपाय है। इसके अलावा भोजन को अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए। यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो उसे अच्छी तरह से पकाने के बाद ही खाना चाहिए। एहतियात बरतने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वहीं, अगर इस बीमारी से जुड़े किसी भी प्रकार के लक्षण दिखें तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें।

विपुल महतो, रांची

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@gmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

मधोश त्यागी, नोएडा

आम बजट से अर्थव्यवस्था पकड़ेगी धीमी रफ्तार



अजय मोहंती

आमजन से बेमेल

यह आम बजट आमजन के लिए कुछ खास नहीं रहा। आयकर दाताओं से सरकार सशर्त कर वसूलना चाहती है। बजट में अगले वर्ष राजकोषीय घाटा अधिक रहने के आसार हैं। आर्थिक वृद्धि कैसे बढ़ेगी इनके निवारण के अभाव से बाजार नाखुश होकर मंदी की ओर बढ़ने लगा। किसानों के प्रति सरकार का रुख ठीक दिखा। परंतु एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने से बीमा करने वालों को भय बना है कि कहीं उनका निवेश खतरे में न पड़ जाए। सब्सिडी पर अंकुश लगाने के फैसले से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नए कर प्रावधानों से ज्यादा लाभ नहीं दिख रहा बल्कि पहले के प्रावधान ज्यादा लाभकारी हैं। बजट में रोजगार आदि के लिए खास प्रावधानों का अभाव है।

विवेकानंद मिश्र
देवरिया, उत्तर प्रदेश

अपेक्षाओं की निराशा

बजट में आर्थिक सुस्ती को सुधारने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए थे, उन्हें नजरअंदाज किया गया है। आयकर दरों में कमी से मध्यम वर्ग के आयकरदाताओं को राहत मिलेगी। यह देkhना होगा कि किसानों को कर्ज और राहत की घोषणाएं यथार्थ के धरातल पर कितनी खरी उतरती हैं। सवाल यह भी है कि जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने से क्या होगा, क्या आए दिन जीएसटी दरों में कमी से करोड़ों का फर्जीवाड़ा रुक पाया है ? सामान्य लोगों की अनिवार्य आवश्यकताओं के प्रति महंगाई को रोकने के लिए क्या किया गया है ? सारांशत: बजट अपेक्षाओं की कसौटी पर पूर्णत: निराशाजनक है और इससे आर्थिक सुस्ती कम नहीं होगी।

एम राज राकेश
अलवर, राजस्थान

चुनौतीपूर्ण समय में संतुलित

इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यह बजट पेश किया है। एक ओर मांग सुस्त है तो दूसरी ओर मुद्रास्फूर्ति की चुनौती भी मुंह बाए खड़ी है। राजकोषीय मोर्चे पर भी मुश्किलें हैं। फिर भी वित्त मंत्री ने कृषि व ग्रामीण विकास, शिक्षा व कौशल विकास और स्वच्छता व पेयजल को विकसित कर उन्नत भारत बनाने का सपना दिखाया है। इस बजट में आम लोगों के साथ-साथ कारोबार जगत का भरोसा बढ़ाने वाले कई कदम उठाए गए हैं। रोजगार सृजन बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी की दर कम करने पर बजट का सकारात्मक प्रभाव होगा। घोषणाओं को लागू करने पर बजट के दूरगामी परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

कल्याण योजनाओं पर केंद्रित

बजट 2020 से यह प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में आर्थिक सुस्ती के दौर में है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हुए उसे मजबूत बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर सार्वजनिक निवेश करने की आवश्यकता है। ताकि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों। मनरेगा के तहत सरकार ने 61,500 करोड़ रुपये की बड़ी रकम आवंटित की है। ग्रामीण भारत की खुशहाली के मकसद से समाज कल्याण की योजनाओं पर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। वर्ष 2020 के बजट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के कल्याण के लिए भी पर्याप्त धन दिया गया है। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी ध्यान दिया है। बजट में नशा मुक्ति को मुहिम को तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत आने वाले वित्तीय वर्ष में 260 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दिपिका शर्मा
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

पुरस्कृत पत्र

अर्थव्यवस्था को गति देने की संभावना कम
आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए उपभोग एवं निवेश में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं है। व्यक्तिगत आयकर में छूट का निर्णय अच्छा है, लेकिन नई कर व्यवस्था से बचत प्रभावित होगी। छोटी एवं घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बजट में लाभांश कर नीति में बदलाव के बाद कंपनियां वैकल्पिक उपायों पर अधिक ध्यान देंगी। इससे विदेशी निवेशकों को लाभ होगा। पहले जहां कंपनियों से इसे वसूलने में आसानी होती थी, वहाँ अब शेरयधारकों की बड़ी संख्या से यह कर वसूलना होगा। इसकी निगरानी करना भी सरल नहीं होगा। ई-कॉमर्स संबंधी लेनदेन पर एक प्रतिशत टीडीएस से ‘डिजिटल इंडिया’ का नारा प्रभावित होने की संभावना है। बजट में ग्रामीण मांग बढ़ाने के 16 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा सकारात्मक है।
पुरस्कार राशि 500 रुपये

बुनियाद मजबूत करने वाला

वित्त मंत्री ने आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने का प्रयास किया है जिससे लंबी अवधि तक अर्थव्यवस्था मजबूत बन सके। ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पर विशेष बल के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बुजुर्ग पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए क्वांटम तकनीक और भारत नेट कार्यक्रम पर भी जोर है। वेतनभोगियों के लिए आयकर ढांचे में बदलाव किया गया है। सरकार कुछ बड़ा करने के चक्कर में बड़ी गलती करने से बची है।
--

अंकित त्रिपाठी
ई-मेल से

परिस्थितियों के अनुरूप

आम बजट में खपत बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण पर बजट बढ़ाया गया है। निर्यात संवंधन के जरिये रोजगार का सृजन करना बजट की प्राथमिकताओं में शामिल है। बैंक डूबने की स्थिति में एक लाख आयकर की संरचना को वैकल्पिक बनाया गया है। इससे करदाता के सम्मुख चयन की समस्या आ गई है और वह दुविधा में है। राजस्व संग्रह में कमी और राजकोषी व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटे को 3.5 फीसदी की प्रस्तावित सीमा में बांधे रखना कठिन हो सकता है। 5 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बजट प्रस्ताव मददगार हो सकते हैं।

अंकित त्रिपाठी
ई-मेल से

कंपनियों को सहूलियत

आम बजट में खपत बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण पर बजट बढ़ाया गया है। निर्यात संवंधन के जरिये रोजगार का सृजन करना बजट की प्राथमिकताओं में शामिल है। बैंक डूबने की स्थिति में एक लाख आयकर की संरचना को वैकल्पिक बनाया गया है। इससे करदाता के सम्मुख चयन की समस्या आ गई है और वह दुविधा में है। राजस्व संग्रह में कमी और राजकोषी व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटे को 3.5 फीसदी की प्रस्तावित सीमा में बांधे रखना कठिन हो सकता है। 5 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बजट प्रस्ताव मददगार हो सकते हैं।

डॉ. एम एस सिद्दीकी
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

कंपनियों को सहूलियत

बजट मुख्य रूप से दो बातों के लिए जाना जाएगा। एक डीडीटी की समाप्ति और दूसरी आयकर के नए प्रारूप। पहले कॉर्पोरेट कर में कमी और अब डीडीटी की समाप्ति से कंपनी के हाथ में अब अधिक नकदी होगी। ऐसे में कंपनियों को चाहिए कि वो इस धनराशि को विस्तार और नए उद्योग लगाने में निवेश करें। लाभांश के जरिये कंपनी प्रवर्तकों के हाथ और धनराशि जाने, सरकारी छूट बेनतीजा हो जाने, आयकर की नई दरें, कर सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। वित्त मंत्री ने पुराने कर ढांचे को आने वाले वर्षों में समाप्त करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से एनएससी, एलआईसी आदि बचत योजनाओं के निवेश पर विपरीत असर पड़ सकता है। बजट में विदेशी निवेश भारतीय बॉन्ड बाजार की ओर आकर्षित हो इसके लिए भी प्रयास नजर आते हैं।

अजीत सिंह चौधरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

मौजूदा समस्याओं का हल नहीं

इस बार के बजट को लेकर बहुत सी आशंकाएं थीं जो बजट के सार्वजनिक हो जाने के बाद और भी बलवती हो गईं। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी, अशिक्षा, अधिक जनसंख्या, गरीबी और सामाजिक ताना बाना जैसे जाति, मजकूर और वर्ण को लेकर मचा घमासान है, आमजन के लिए बजट जैसी वित्तीय महत्ता की बातों को समझना दुरूह ही है। वैसे इस बार स्टार्टअप पर 100 करोड़ तक के टर्न ओवर पर छूट एक अच्छी पहल है और 2 साल में ढाई लाख सरकारी नौकरी का वादा तो सोने पे सुहागा है, पर आयकर के दो विकल्प उलझाने वाला ज्यादा है और जटिल भी। बैंक, रियल एस्टेट, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन अच्छा है पर कई प्रकार की छूट आदि का हटना नाजायज है। आयकर को और आकर्षक बनाया जाना चाहिए क्योंकि मध्य आय वर्ग की कमर टूट चुकी है।

डॉं आंजनेय गुप्ता
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

आर्थिक सुस्ती से उबारने वाला
आर्थिक सुस्ती के बीच पेश यह बजट दर्शाता है कि संगठित और योजनाबद्ध नियोजन से देश इस मंदी के चक्र से बाहर आ सकता है। कृषि विकास को इस बजट ने महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है क्योंकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की मांग का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों से ही आता है। जैविक खेती को बढ़ावा देना, 100 सूबा पीढ़ित जिलों में जल संचयन की सुविधा का विस्तार करना, बीज से जुड़ी धन्य लक्ष्मी योजना से महिलाओं को जोड़ना, मालगाड़ियों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ऐसी ही अनेक योजनाएं हैं जिनसे किसान लाभान्वित हो सकते हैं।

रविंद्र प्रकाश
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

कम आय वालों के लिए कुछ नहीं

देश के हर वर्ग को कोई खुश नहीं कर सकता। आज महंगाई ने आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। आम बजट पर विशेषज्ञ मात्र आयकर की छूट पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन लोगों की आय बढ़ाने, बेरोजगारों को आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किए, इस पर कोई खास नहीं बोल रहा ? जबकि हमारे देश में मजदूरी और निजी क्षेत्र में कम आय वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आयकर की आय की सीमा में बढ़ोतरी होती रहेगी तो खजाना कैसे भरेगा ? बजट ऐसा होना चाहिए था जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ हो।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

अर्थव्यवस्था को अधर में छोड़ा

राजकोषीय घाटा 3.8 लाख करोड़ से घटकर इस वर्ष 3.5 लाख करोड़ करने की कवायद हो तो रही है पर इसकी गुंजाइश कम ही है। आयकर में दो तरह की कर व्यवस्था से मध्य आय वर्ग का असमंजस में है जिसका खमियाजा अर्थव्यवस्था को भरना होगा। एलआईसी का हिस्सा बेचना इसकी साख को गिराना है। सब्सिडी जरूरी जगहों से हटाना ठीक नहीं था। रेलवे को निजीकरण की तरफ करके 70,000 करोड़ रुपये का आवंटन भी समझ से परे है। बजट में की गई आंकड़ों की बाजीगरी अर्थव्यवस्था को अधर में छोड़ देगी।

दिव्या ‘प्रीत’ सेठी
नोएडा, उत्तर प्रदेश

उम्मीदों भरा बजट

अमूमन हर वित्त मंत्री का प्रयास होता है कि समाज के सभी तबकों को कुछ न कुछ देकर संतुष्ट किया जाए। लेकिन सबको खुश करना नामुमकिन है। वित्त मंत्री ने सुशिक्षित समाज, जल संरक्षण, जनसंख्या नियोजन, गरीबी उन्मूलन, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ समाज, उद्योगों की उन्नति और बेहतरी की राह आदि पर अच्छी खासी राशि आवंटित की है। इतना ही नहीं विभिन्न छूटों सहित और रहित आयकर का नया स्लैब इजाज करके वित्त मंत्री ने सभी श्रेणी के करदाताओं को नए और पुराने स्लैबों में से उनके फायदे का स्लैब चुनने का मौका दिया है जिसे इस बजट की विशेषता ही कहा जा सकता है। संक्षेप में बजट से बड़ी आशाएं पालने वालों को निराशा और लंबे भविष्य के बारे में सोचने वालों के लिए उम्मीदों का दूरदर्शी बजट है।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

आर्थिक सुधारों को मिलेगा बल

केंद्र सरकार के आर्थिक सुधारों के चरण का प्रत्यक्ष असर हालिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-21 में दिखाई दे रहा है। चाहे वह किसानों के लिए घोषित 16 सूत्रीय एजेंडा हो, कृषि से जुड़े उत्पादों के लिए कृषि उड़ान व किसान रेल जैसे परिवहन का माध्यम हो या फिर महिलाओं, दिव्यांगों के लिए निधियों के निर्धारण के प्रावधान हों। सुधारों की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। सुधार सदैव तात्कालिक समस्या होता है लेकिन परोक्ष रूप से दीर्घकाल के लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। बहरहाल इस वर्ष सुधारों के परिणाम दिखने की उम्मीद है लेकिन वैश्विक आर्थिक सुस्ती, कोरोनावायरस से उठे वैश्विक संकट के साथ ही अन्य अप्रत्याशित संकटों से यह धूमिल भी हो सकती है।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी
उज्जैन, मध्य प्रदेश

मिला जुला बजट

यह बजट एक साकारात्मक दिशा में जाने वाला बजट है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि आगे भी ले जाएगा। राजकोषीय घाटे को कम करने के वैसे तो हर आम बजट में उपाय होते हैं पर इस बार जमीन को पकड़ के वित्तमंत्री ने न सिर्फ किसानों, गरीबों और बेरोजगारों को सशक्त किया बल्कि व्यवसायी वर्ग को भी स्टार्टअप और कई प्रकार की प्रोत्साहन स्कीम की सौगत दी है। आयकर ढांचे का दो श्रेणियों में वर्गीकरण अच्छी पहल है जिससे मध्य आय वर्ग लाभान्वित होगा। बजट में इस बार रोजगार और गरीबी की समस्याओं का कोई समाधान नहीं सुझाया गया है और आईटीबीआई तथा एलआईसी के बेचे जाने का भ्रम लोगों में बढ़ाया गया है।

डॉं राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

श्रेष्ठ पत्र

रूबी सिंह
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

मनोहर उपाध्याय
इंदौर, मध्य प्रदेश

संतोषजनक है बजट

वित्त मंत्री ने बजट में आयकर ढांचे में बदलाव कर मध्य वर्ग को राहत दी है। कंपनियों के लिए लाभांश वितरण समाप्त कर चीजों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। बजट में राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान देने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए 4,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने बजट में स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देकर बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस आम बजट से बाजार की सुस्ती टूटेगी। हालांकि बजट में सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जिसका असर अभी नहीं दिखाई देगा। बजट में महंगाई रोकने के उपायों का अभाव है। वित्त मंत्री ने इस बजट में दूरगामी प्रभाव के लिए आय और व्यय के संतुलन को बनाए रखने का भरपूर प्रयत्न किया है। कुल मिलाकर बजट संतोषजनक है।

बकौल विश्लेषक
छोटे उद्योगों को मिलेगी राहत, अर्थव्यवस्था में होगा सुधार
आम बजट 2020-21 में लघु उद्योगों के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। छोटे एवं मझोले उद्योगों के लिए सबऑर्डिनेट कर योजना से एमएसएमई उद्योगों के सामने आने वाली कार्यशील पूंजी की कमी की समस्या दूर होगी। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत छोटे और मझोले कारोबारियों को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले कर्ज पुनर्गठन की समयसीमा 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही थी लेकिन केंद्र सरकार ने बजट प्रस्ताव में केंद्रीय बैंक से इसे एक वर्ष और बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि हमारा मानना है कि उपयुक्त लगने वाले कुछ एनपीए खातों का भी एक बार पुनर्गठन किया जाए। हालांकि कारोबार को सुगम बनाने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) को लाया गया है लेकिन यह फिलहाल शुरुआती चरण में ही है और अभी कई बड़ी कंपनियों तथा कारोबारियों ने इसमें अपना पंजीकरण नहीं कराया है। बजट 2021 में ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है जो एक अच्छा कदम है। हालिया बजट में 25 करोड़ रुपये तक की टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे स्टार्टअप कंपनियों को बड़ा समर्थन मिल सके। हालांकि इसके क्रियान्वयन या स्टार्टअप की पहल में तेजी लानी होगी क्योंकि पिछले रिकॉर्ड के अनुसार केवल एक प्रतिशत पंजीकृत स्टार्टअप ही कर में छूट का लाभ ले सके। एमएसएमई समेत छोटे उद्यमियों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने कर लेखा परीक्षण के लिए एक करोड़ रुपये की मौजूदा टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह बढ़ी हुई सीमा केवल ऐसे व्यवसायों पर लागू होगी जो अपने व्यापार लेनदेन में पांच प्रतिशत से कम नकदी का इस्तेमाल करते हैं। इस पहल से लघु उद्यमी मुख्य धारा में आ जाएंगे, जिससे उन्हें औपचारिक वित्त जुटाने में भी मदद मिलेगी। हमारा मानना है कि आम बजट 2020-21 में छोटे तथा मझोले क्षेत्र समेत दूसरे क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
बातचीत: वीरेश्वर तोमर

मुकेश मोहन गुप्ता
अध्यक्ष, बैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज

स्थिरता भरा रहा आम बजट
आम बजट 2020-21 व्यक्तिगत करदाताओं के पास कर ढांचे के दो विकल्प उपलब्ध कराने के अलावा लगभग स्थिर रख वाला रहा। हालांकि यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में सभी लोग नए कर ढांचे में शामिल हो जाएंगे जिसका अर्थ होगा कम दरें उपलब्ध कराते हुए किसी भी तरह की छूट को समाप्त करना। लाभांश वितरण कर को हटाए जाने से कंपनियों को लाभ होगा लेकिन लाभांश का लाभ लेने वाले अधिकांश व्यक्तियों का आयकर की उच्च दर वाली स्लैब में आने से इस कदम का व्यक्तिगत स्तर पर नकारात्मक असर होगा। यह देश में समानता की संस्कृति विकसित करने के हिसाब से सही नहीं है। सड़क तथा रेलवे के अलावा कृषि तथा सोशल खर्च पर भी छूट जारी रखी गई जिससे निवेश को गति मिलेगी। सरकार ने नरेगा जैसी नकद हस्तांतरण संबंधी योजनाओं के लिए बड़े लक्ष्य तय नहीं किए हैं। इस बार राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रखने का लक्ष्य तय किया गया है जिसे हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इसका प्रत्यक्ष आधा 2.1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य है और पहले कभी भी यह आंकड़ा हासिल नहीं किया गया है। बजट में एलआईसी में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा बड़ी खबर है, और अगर इसे पूरा कर लिया जाता है तो पूंजी बाजार को गति मिलेगी। सकल उधारी को 5.1 लाख करोड़ रुपये रखने (पिछले वर्ष 4.74 लाख करोड़ रुपये) से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि तरलता की कमी नहीं होगी। उद्योग के नजरिये से कई उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। इससे बाजार में आयातित उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इसका उद्देश्य गैर-जरूरी सामान के आयात को हतोत्साहित करना और घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान करना है। सार के तौर पर बजट 2020-21 एक स्थिर बजट की तरह दिखाई दे रहा है जो राजकोषीय राह से भटकें बिना एफआरबीएम ढांचे के तहत निवेश के रास्ते उपलब्ध करा रहा है।
बातचीत: वीरेश्वर तोमर

मदन सबनवीस
मुम्बय अर्थशास्त्री, केयर रेटिंक्स

स्थिरता भरा रहा आम बजट

आम बजट 2020-21 व्यक्तिगत करदाताओं के पास कर ढांचे के दो विकल्प उपलब्ध कराने के अलावा लगभग स्थिर रख वाला रहा। हालांकि यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में सभी लोग नए कर ढांचे में शामिल हो जाएंगे जिसका अर्थ होगा कम दरें उपलब्ध कराते हुए किसी भी तरह की छूट को समाप्त करना। लाभांश वितरण कर को हटाए जाने से कंपनियों को लाभ होगा लेकिन लाभांश का लाभ लेने वाले अधिकांश व्यक्तियों का आयकर की उच्च दर वाली स्लैब में आने से इस कदम का व्यक्तिगत स्तर पर नकारात्मक असर होगा। यह देश में समानता की संस्कृति विकसित करने के हिसाब से सही नहीं है। सड़क तथा रेलवे के अलावा कृषि तथा सोशल खर्च पर भी छूट जारी रखी गई जिससे निवेश को गति मिलेगी। सरकार ने नरेगा जैसी नकद हस्तांतरण संबंधी योजनाओं के लिए बड़े लक्ष्य तय नहीं किए हैं। इस बार राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रखने का लक्ष्य तय किया गया है जिसे हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इसका प्रत्यक्ष आधा 2.1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य है और पहले कभी भी यह आंकड़ा हासिल नहीं किया गया है। बजट में एलआईसी में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा बड़ी खबर है, और अगर इसे पूरा कर लिया जाता है तो पूंजी बाजार को गति मिलेगी। सकल उधारी को 5.1 लाख करोड़ रुपये रखने (पिछले वर्ष 4.74 लाख करोड़ रुपये) से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि तरलता की कमी नहीं होगी। उद्योग के नजरिये से कई उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। इससे बाजार में आयातित उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इसका उद्देश्य गैर-जरूरी सामान के आयात को हतोत्साहित करना और घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान करना है। सार के तौर पर बजट 2020-21 एक स्थिर बजट की तरह दिखाई दे रहा है जो राजकोषीय राह से भटकें बिना एफआरबीएम ढांचे के तहत निवेश के रास्ते उपलब्ध करा रहा है।

मदन सबनवीस
मुम्बय अर्थशास्त्री, केयर रेटिंक्स

मदन सबनवीस
मुम्बय अर्थशास्त्री, केयर रेटिंक्स

मदन सबनवीस
मुम्बय अर्थशास्त्री, केयर रेटिंक्स

... और यह है अगला मुद्दा
हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय। इस बार का विषय है – आयकर की दोहरी प्रणाली कितनी सुगम? अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फ़ैक्स नंबर- 011-3720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in

बीमा दावे के लिए बाढ़ में बारिश भी शामिल

एमजे एंटनी

भारी बारिश के साथ संपत्ति को हुए नुकसान को साधारण बीमा नीति में बाढ़ और सैलाब की परिभाषा में शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी की दलील को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है।

कंपनी का कहना था कि यह बीमा नीति के दायरे से बाहर है। उसकी दलील थी कि भारी और असाधारण बारिश से हुआ नुकसान बीमित नहीं है। दरअसल भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जेके सीमेंट वर्क्स का नीमबेहरा में रखा कोयला भंडार बरबाद हो गया था। बाढ़ और सैलाब की पेचीदा दलील पर बीमा कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया।

बीमा कंपनी को जिला उपभोक्ता फोरम से लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने भी उसके दावों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस इलाके में भारी बारिश हुई थी जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे।

इससे कंपनी के परिसरों में रखा कोयला खराब हो गया। सर्वेयर की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारी बारिश के कारण वहां पानी जमा हो गया था जिससे खराब हो गया। न्यायालय ने ओरियंटल को नौ फीसदी ब्याज के साथ 58.89 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

बीमा कंपनी को चोरी की रिपोर्टिंग में देरी

उच्चतम न्यायालय ने वाहन चोरी की सूचना देरी से बीमा कंपनी को देने के सवाल पर दो न्यायाधीशों के मतभेदों को सुलझाते हुए कहा है कि इस तरह की देरी दावे को खारिज करने के लिए आधार नहीं हो सकती है। न्यायालय ने गुरशिंदर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी वाद में यह व्यवस्था दी। सिंह का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की लेकिन वाहन का पता नहीं चल पाया। उन्होंने बीमा कंपनी में दावा किया लेकिन 52 दिन की देरी का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया गया। उपभोक्ता फोरमों और राष्ट्रीय आयोग ने भी इसी आधार पर दावे को खारिज कर दिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनके फैसले को पलटते हुए कहा कि जब किसी बीमित व्यक्ति ने चोरी के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पुलिस ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दे दी है कि वह वाहन खोजने में नाकाम रही है और जब बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर ने वाहन चोरी के दावे को सही पाया है तो बीमा कंपनी को सूचना में देरी दावे को खारिज करने के आधार नहीं हो सकता है।

पट्टे की जमीन : पेट्रो कंपनियों की हार

उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन पेट्रोलियम कंपनियों की अपील को खारिज कर दिया है जो चाहती थीं कि अदालत भूमालिकों को उन्हें पट्टे की जमीन बेचने का निर्देश दे। इन कंपनियों ने बहुत पहले पेट्रोल पंप बनाए थे और डीलरशिप समझौते के तहत उन्हें डीलरों को दिया था। डीलरों को दी गई जमीन का वास्तविक कब्जा कंपनियों के पास नहीं था।

पट्टे में समयसीमा का कोई उल्लेख नहीं था। कंपनियां चाहती थीं कि न्यायालय जमीन की कोमत तय करे और भूखंड उन्हें बेच दे। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अपने दावे को सही ठहराने के लिए मद्रास शहर किरायेदार संरक्षण अधिनियम का सहारा लिया। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था क्योंकि जमीन का वास्तविक कब्जा उनके पास नहीं था लेकिन उन्होंने इसे डीलरों को दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इसे सही ठहराया।

गिफ्ट वाउचर के साथ जुड़ी हैं शर्तें

कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के साथ शर्तें जुड़ी होती हैं। टाटा मकैन्डाइज बनाम अनिल कुमार वाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले में एक बार फिर यह बात साबित हुई है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर



हॉलिडे वाउचर का प्रचार किया था कि इससे खरीदारों को लैपटॉप, सेलफोन और एलईडी टीवी जैसे उपहार मिलेंगे। इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई थीं। इस खरीदार ने तीन वाउचर खरीदे और इन पर उपहार का दावा किया। कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया क्योंकि वह शर्तों को पूरा नहीं करता था। खरीदार ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और यह दलील दी कि निराशा के कारण उसे मानसिक प्रताड़ना हुई है।

फोरम ने उनकी दलील को मान लिया। मुआवजे के आदेश के खिलाफ कंपनी की अपील खारिज हो गई। लेकिन अपनी अंतिम अपील में कंपनी अपने खिलाफ सभी आदेशों को पलटने में सफल रही। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दूसरी शर्तें पूरी किए बिना केवल वाउचर खरीदने से ही खरीदार उपहारों का हकदार नहीं बन जाता है।

अनुबंध मध्यस्थता में सरकार की हार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जी। लिटमस इवेंट्स लिमिटेड के खिलाफ विवाद में पंचाट के फैसले को चुनौती देने वाली युवा मामलों के मंत्रालय की अपील दूसरी बार खारिज कर दी है। यह विवाद दिल्ली में करीब 10 साल पहले हुए राष्ट्रमंडल खेलों में दिए गए ठेकों से जुड़ा है।

कंसोर्टियम ने बकाये का भुगतान नहीं किया जाने की शिकायत की थी और पंचाट का फैसला सरकार के खिलाफ आया था। सरकार ने पिछले साल इसके कुछ हिस्सों को सितंबर में करीब 10 साल पहले हुए राष्ट्रमंडल खेलों में दिए गए ठेकों से जुड़ा है।

कंसोर्टियम ने बकाये का भुगतान नहीं किया जाने की शिकायत की थी और पंचाट का फैसला सरकार के खिलाफ आया था। सरकार ने पिछले साल इसके कुछ हिस्सों को सितंबर में करीब 10 साल पहले हुए राष्ट्रमंडल खेलों में दिए गए ठेकों से जुड़ा है।

सरकार ने दलील थी कि अनुबंध के तहत उसकी मुआवजा और ब्याज देने की जिम्मेदारी नहीं थी। न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि पंचाट ने पाया कि कंपनी को यह राशि पाने का अधिकार था और इसके लिए पर्याप्त सबूत भी रखे गए थे। लेकिन उसे अवैध रूप से इससे वंचित रखा गया। न्यायालय ने साथ ही कहा कि पंचाट के फैसलों के खिलाफ अपील में उसकी भूमिका सीमित है।

विक्रेताओं की मुकदमेबाजी

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने विक्रेताओं के एक पक्ष के खिलाफ लगाई गई रोक हटा दी है। एकल पीठ ने यह पाबंदी लगाई थी। दावा किया जा रहा था कि यह पक्ष सीधे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री कर रहा है। एमेज़ॉन सेलर सर्बिसेज ने एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज, ओरिफ्लेम इंडिया और मोदीकेयर लिमिटेड के खिलाफ तीन अपील दायर की थीं। इनमें से दो अपील क्लाउडटेल इंडिया लिमिटेड ने क्रमशः एमवे और ओरिफ्लेम के खिलाफ की थी।

एक अपील स्नैपडील ने एमवे के खिलाफ की थी। इसमें विवाद यह था कि एमवे के उत्पाद विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिये बेचे जा रहे थे। थोक और खुदरा दुकानों में अवैध तरीके से छूट दे रही थीं जिससे एमवे के उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं की बिक्री में कमी आ रही थी। यह आरोप भी था कि इस तरह के अवैध विक्रेता एमवे के उत्पादों पर प्रकाशित विशेष कोड को हटा रहे थे ताकि उन्हें पकड़ा न जा सके। एकल न्यायाधीश ने पाया कि इसमें अनुबंध का उल्लंघन हुआ था। खंडपीठ ने कहा कि विपक्षी पक्षों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है।

करदाता चार्टर से भर पाएगी भरोसे की खाई ?

अधिकतर घरेलू एवं विदेशी करदाता भारतीय कर व्यवस्था को आक्रामक मानते हैं। ऐसे में एक चार्टर बनाकर उनका भरोसा बहाल की करने की कोशिश की गई है।

ऐश्ली कुटिन्हो और सुदीप्त दे

बजट में आयकर अधिनियम में एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(सीबीडीटी) को एक करदाता चार्टर अपनाने एवं घोषित करने के लिए अधिकृत करता है। आयकर अधिनियम में नई धारा 119ए जोड़े जाने के बाद सीबीडीटी के पास आयकर अधिकारियों को दिशानिर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति मिल जाएगी। अगर इस बजट प्रस्ताव को संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी।

भारत को अक्सर घरेलू एवं बाहरी करदाता एक आक्रामक कर नियमन वाले देश के तौर पर देखते रहे हैं। ऐसे में करदाताओं के लिए तैयार चार्टर को इस कानून का हिस्सा बनाने से करदाताओं का भरोसा बहाल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि बाजार से जुड़े लोगों को लगता है कि इस चार्टर का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस तरह तैयार एवं लागू किया जाता है ?

बोएसआर लीगल के प्रबंध निदेशक मुकेश बुटानी कहते हैं कि एक करदाता चार्टर का कानून में प्रावधान होना आयकर विभाग की वेबसाइट पर उल्लिखित सिटिजंस चार्टर से काफी आगे की बात है। सिटिजंस चार्टर में भी पारदर्शिता एवं सेवा मानदंडों के लिए सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख है लेकिन उसमें असरकारी क्षमता की कमी है। ऐसे में नए चार्टर को तैयार करते समय कानून-निर्माताओं को करदाताओं के प्रति एक तरह की जवाबदेही दिखानी चाहिए। बुटानी का मानना है कि करदाता चार्टर में कर विवरण सूचना की निजता, कारोबार संबंधी आंकड़ों की गोपनीयता और औपचारिक समाधान प्रक्रिया से इतर एक शिकायत निपटान प्रणाली को भी शामिल किया जाना चाहिए।

बुटानी कहते हैं, ‘भारत में अदालतों ने एक समृद्ध प्रणाली तय की हुई है ताकि अधिकारी न्यायपूर्ण ढंग से आचरण करें। अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो अधिकारियों के भीतर जवाबदेही की भावना लाने की भी जरूरत है। इस लक्ष्य को करदाता चार्टर से ही हासिल किया जा सकता है।’

आरएसएम इंडिया के संस्थापक सुरेश सुराना का मानना है कि चार्टर के भीतर क्रियान्वयन में एकरूपता रखी जानी चाहिए

सिटिजंस चार्टर

■ **आयकर अधिनियम में नई धारा 119ए जोड़े जाने के बाद सीबीडीटी के पास आयकर अधिकारियों को दिशानिर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति मिल जाएगी**

■ **बजट प्रस्ताव को संसद की स्वीकृति मिलने पर नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी**

■ **दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में ऐसे ही करदाता चार्टर बने हुए हैं**

■ **ब्राजील और इटली जैसे देशों में यह चार्टर कानून का हिस्सा है**

■ **ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में चार्टर को विधिक संरक्षण नहीं मिला है**

ताकि प्रशासनिक विवेक की गुंजाइश ही न रहे और इसका अनुपालन न होने पर वैधानिक उपचार का भी प्रावधान हो।

अद्वैत लीगल के वरिष्ठ प्रमुख (प्रत्यक्ष कर मामला) अरिजीत चक्रवर्ती कहते हैं कि एक चार्टर भले ही करदाता को अधिकार दे देगा लेकिन उसके प्रभावी होने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है। चक्रवर्ती कहते हैं, ‘अभी तक का हमारा अनुभव इसके ठीक उलट है। करदाताओं को संदेह की नजर से देखा जाता है, उठने वाले मुद्दे कभी भी अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, एक कारगर निपटान व्यवस्था का अभाव है और सबसे अहम, उठाए गए कदम के लिए जवाबदेही की कमी है।’

जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में ऐसे ही करदाता चार्टर बने हुए हैं। ब्राजील और इटली जैसे देशों में यह चार्टर कानून का हिस्सा है जबकि



अजय मोहंती

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में चार्टर को विधिक संरक्षण नहीं मिला है। ट्रांजैक्शन स्ववायर के संस्थापक गिरीश वनवारी को लगता है कि इस चार्टर का प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि यह आयकर अधिनियम के प्रशासकीय पहलुओं पर किस तरह असर डालता है और करदाताओं की आक्रामक कर योजना एवं राजस्व अधिकारियों को कर आक्रामकता के बीच किस तरह संतुलन साधता है ? वनवारी कहते हैं, ‘यह देखना भी रोचक होगा कि यह चार्टर अधिनियम में पहले से ही मौजूद विवाद निपटान प्रणाली के भीतर किस तरह काम करता है ?’

कानूनी जानकारों का मानना है कि नए चार्टर में कई बिंदुओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए जाने की जरूरत है। मसलन, तलाशी लेने या सम्यक रूप से अधिकृत जांच को छोड़कर समन जारी करने या कर प्रक्रिया चलने पर विशिष्ट मुद्दों का जिक्क करते हुए एक पूर्व-नोटिस व्यवस्था की जरूरत है। सुराना कहते हैं कि समन जारी होने, तलाशी या सर्वे के दौरान करदाताओं को अपने कानूनी या कर सलाहकार साथ रखने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह बयान दर्ज कराते समय भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा एक तय समय से अधिक पूछताछ चलने पर करदाताओं के पास निजता का अधिकार और दवा लेने, पूजा करने, सोने और आकस्मिक जरूरतों के लिए भी छूट मिलनी चाहिए।

मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अमित पटेल कहते हैं, ‘अपीलों के निपटारे की समय-सीमा तय की जानी चाहिए। मसलन, अगर मैं आयकर आयुक्त के समक्ष कोई अपील करता हूं और उसकी सुनवाई दो-तीन या पांच साल में नहीं होती है तो फिर यह एक

समस्या है।’

शार्दूल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर अभय शर्मा चाहते हैं कि कर प्रमाण-पत्र जारी करने की एक तय समय-सीमा रखी जाए और जुर्माना लगाने की परिपाटी पर रोक लगाई जाए, बशर्तें कि करदाता ने कर चोरी की हो। वह कहते हैं, ‘एक कर मामले में शीर्ष अदालत की तरफ से निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने से इनकार करने को हतोत्साहित या रोक लगानी चाहिए। दो तरह के विचार होने पर करदाता के लिए लाभप्रद सोच ही लागू करने का सिद्धांत आत्मसात करना होगा।’

ईवाई इंडिया के राष्ट्रीय कर प्रमुख सुधीर कपाडिया की मानें तो एक चार्टर को तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में लागू करने की जरूरत है लेकिन कानून में सभी संभव व्यावहारिक स्थितियों के लिए एक बहुदेशीय प्रावधान कर पाना मुश्किल होगा। वह कहते हैं, ‘इस तरह के चार्टर का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि वरिष्ठ कर अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न होने पर करदाता इन दिशानिर्देशों का हवाला दे सकें। अपील की अधिकरणों और अदालतों में मामला जाने पर भी करदाता इनका उल्लेख कर सकते हैं।’

वनवारी का मानना है कि घरेलू एवं विदेशी दोनों स्तरों पर कराधान परिदृश्य में मौजूदा प्रवाह को देखते हुए यह चार्टर लागू करने का वक्त अहम होगा। ‘भारत डिजिटलीकरण और ई-आकलन के संक्रमण काल से गुजर रहा है। इसके साथ आयकर अधिनियम में नियंत्रण एवं संतुलन भी लगातार बढ़ रहा है। सामान्य करवंचना-रोधी नियम, नोटबंदी और डिजिटल प्रयोग से कर चोरी रोकने की कोशिशें हुई हैं। ऐसी स्थिति में करदाता चार्टर लाने के पहले समुचित विमर्श की जरूरत है।’

कृत्रिम मेधा के नियमन में दिखाना होगा नयापन

कृत्रिम मेधा संबंधी नियमों के प्रति उद्योग-केंद्रित नजरिया अपनाने से नियामकों को काफी लचीलापन मिलेगा



गूगल की संचालक कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कार्योधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने कृत्रिम मेधा (एआई) के नियमन की जरूरत पर बल देकर इस मामले में फिर से बहस छेड़ दी है। पिचाई के पहले टेस्ला के एलन मस्क भी पिछले कई साल से इसकी वकालत करते रहे हैं। फिर भी पिचाई के इस बयान का वक्त काफी अहम है।

चेहरें की शिनाख्त जैसे एआई-आधारित अनुप्रयोगों का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में तेजी से बढ़ रहा है और उसी तेजी से उनका विकास भी हो रहा है। एआई तकनीक की हमेशा बदलती रहने वाली प्रकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसके नियमन के नियम अनुप्रयोग पर आधारित होने चाहिए।

कानूनी फर्म जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर संजय सिंह एआई के नियमन का सवाल आने पर दुनिया भर के नियामकों के समक्ष पैदा होने वाली दुविधा का जिक्क करते हैं। वह सवालिया अंदाज में कहते हैं, ‘एआई नियमन पर हमारे पास क्या विकल्प हैं ? क्या वह मशीन लर्निंग (एमएल) एवं एआई मॉडलों के परिचालन से संबंधित मुक्त, सार्वभौम एवं पारदर्शी मानकीकृत नियम हैं ? या फिर सभी संबंधित पक्षों के बीच होने वाला कोई समझौता ?’ हालांकि वह कहते हैं कि एमएल या एआई को नियंत्रित किए बगैर इनका नियमन लोग ही असंभव है। लेकिन नियंत्रण हटें भी नियमन का मकसद धरा रह जाएगा।

टेकलीगिंस के प्रबंध साझेदार सलमान वारिस इस राय से इत्फाक रखते हुए कहते हैं कि एआई तकनीक

पर क्षैतिज नियमन होने से नवाचार सीमित हो जाएगा जिससे कानून तकनीकी बदलावों के हिसाब से कानून को ढाल पाना मुश्किल होगा। वारिस कहते हैं, ‘संबंधित उद्योग के हिसाब से एआई का नियमन करने पर अधिक लचीलापन, बेहतर क्रियान्वयन और एक लक्षित परिप्रेक्ष्य संभव हो सकेगा।’

विशेषज्ञ स्टार्टअप पात्रिस्थितिकी बनने से एआई उत्पाद पेश करने के मोर्चे पर भारत में एआई के इर्दगिर्द एक नियामकीय ढांचा खड़ा करने की जरूरत भी बताते हैं। लेकिन अधिकतर जानकार प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक के संदर्भ में कोई नया मानक लाने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि निजता एआई को प्रभावित करने वाला महज एक पहलू है। निशीथ देसाई एसोसिएट्स में विध्वंसक विधेयक का व्यापक एवं वृहद ढांचा तवावाला कहते हैं, ‘डेटा संरक्षण विधेयक का व्यापक एवं वृहद ढांचा होना चाहिए। बाद में हम उद्योग-केंद्रित कानून भी बना सकते हैं, मसलन रोबोटिक्स से लेकर ड्रोन और स्वास्थ्य देखभाल तक।’

तवावाला जवाबदेही के मानक तय करने और एआई अधिकार तय करने की जरूरत पर भी बल देते हैं। वह कहते हैं, ‘सऊदी अरब ने ट्यूमेनॉड रोबोट सौफिया को अपना नागरिक घोषित करने के साथ ही उसे अधिकार भी दिए हैं। लेकिन वह एक अलहदा मामला है। सवाल अब भी यही है कि एआई का स्वामित्व किसके पास है ? अल्गोरिद्म बनाने वाले के पास या उनके संचालक के पास ?’

विशेषज्ञ कहते हैं कि कंपनी संगठनों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं और वे अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह भी हैं। एआई के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक पेच यह है कि कंपनी समूह सही मायने में स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि उनका संचालन ईसान ही करते हैं। वहीं एआई वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं।

सिंहनाहा दुनिया भर की सरकारों के सामने एआई के नियमन पर क्या विकल्प रह जाते हैं ? ट्राईलीगल के पार्टनर राहुल मत्थन कहते हैं, ‘नियमन की प्रकृति अनावश्यक रूप से दंडात्मक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका

नवाचार पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। नियम ऐसे हों कि कंपनियों को नवाचार की छूट हो, नासमझी में हुई गलतियों को माफ करे और केवल लापरवाही में या जानबूझकर की गई गलतियों पर ही सजा मिले।’

भारत सरकार एआई तकनीक के संभावित इस्तेमाल का दोहन करने में काफी सजग रही है। पीयूष गोयल ने पिछले साल का अंतरिम बजट पेश करते समय कहा था कि सरकार एआई को समर्पित एक राष्ट्रीय केंद्र बनाने के बारे में सोच रही है। नीति आयोग ने भी 2018 में जारी अपने एक विमर्श पत्र में कहा था कि भारत को कृत्रिम मेधा की लहर का फायदा उठाने के लिए एक टोस बौद्धिक संपदा प्रारूप की जरूरत है।

कुछ जानकार एआई नियमन के प्रारूप पर एक वैश्विक सहमति चाहते हैं और इसके लिए वे शोध एवं विकास के क्षेत्र में सक्रिय नियामकीय सिंद्धाओं

के बीच संवाद का एक सझा बिंदु बनाने की बात करते हैं। कई लोगों को लगता है कि कानून आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के निष्पक्ष सूचना परंपरा सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। ये

सिद्धांत एआई प्रणालियों को इस तरह बनाने की मांग करते हैं जिनमें विधि के शासन, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विविधता को अहमियत दी गई हो। इसके अलावा एआई प्रणालियों को निजता का भी ध्यान रखना चाहिए।

इस पहली का एक और पहलू भी है: दुनिया भर की सरकारों ने चेहरा पहचानने वाली तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल और दुरुपयोग किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले में खुद एक हितधारक होने के नाते सरकारों नियम-कायदे तय करने में कितनी निष्पक्ष हो पाएंगी ? वारिस कहते हैं, ‘सरकार के लिए तकनीक के इस्तेमाल को संयमित रखने का इकलौता कारगर रास्ता इसके उपयोग में वह खुद अतिसक्रिय रहे। आज जरूरत इस बात की है कि चेहरा शिनाख्त तकनीक के समुचित उपयोग को नियमित करने के लिए सरकार खुद पहल करे।’

विशेषज्ञों का मानना है कि एक विस्तृत नियामकीय ढांचा आने से न केवल आखिरी उपभोक्ता को लाभ होगा बल्कि उद्योग जगत भी एआई तकनीक को बढ़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित होगा।

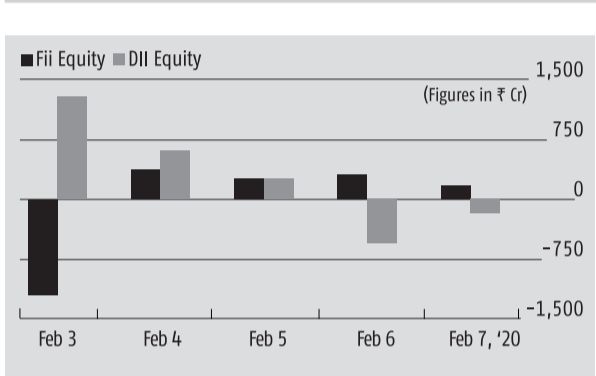
एनएसई डेरिवेटिव में एफआईआई निवेश

	Week ended Feb 1		Week ended Feb 7, 20	
	Contract (Nos)	Tovr (₹bn)	Contract (Nos)	Tovr (₹bn)
Index Future	1030360	827.6	549766	418.2
Stock Future	4998836	3355.9	2048642	1362.5
Index Option	43211674	30449.7	44413991	31154.7
Stock Option	900987	658.4	719800	509.9
Total	50141857	35291.6	47732199	33592.3

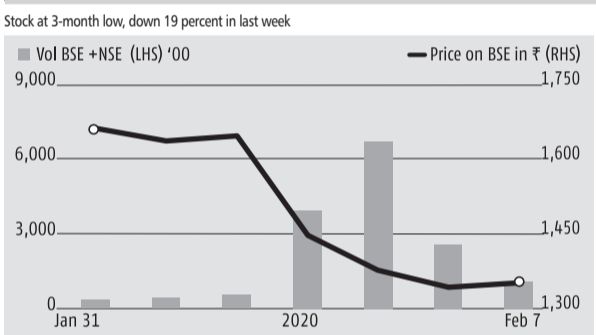
बीएसई 500 कंपनियों में एफआईआई शेयरधारिता

IN %	DEC '18	MAR '18	JUN '19	SEP '19	DEC '19
Vedanta	15.8	16.5	17.0	17.1	16.4
Shree Cement	13.1	13.0	12.2	11.9	13.2
SRF	19.2	17.1	18.2	18.5	18.4
Siemens	2.7	2.3	2.1	2.2	4.3
Supreme Industries	7.0	8.5	8.4	8.1	8.2
Tata Chemicals	10.8	10.1	10.7	9.4	9.8
Tata Power Company	26.1	26.6	26.0	24.2	21.0
Tata Global Beverages	24.7	25.4	26.6	27.8	26.0
Tata Motors	19.0	19.1	19.5	19.0	18.3
Tata Steel	15.0	14.6	13.8	13.6	15.3
Jubilant Life Sciences	24.9	26.7	27.0	27.2	27.4
Voltas	14.6	13.7	13.0	10.2	10.9
Wipro	8.5	8.9	8.2	8.4	8.4
Apollo Hospitals Enter.	47.1	44.3	44.0	47.7	48.8
Dr Reddys Laboratories	29.7	30.9	30.7	30.1	30.0
Titan Company	18.5	19.2	19.6	18.8	18.3
Honeywell Automation	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
State Bank of India	9.2	9.7	10.7	10.7	10.8
Godrej Industries	11.9	12.1	11.9	11.9	12.0
Shriram Trans. Fin. Co.	49.3	50.9	56.4	60.8	64.3
3M India	8.3	8.3	8.3	6.8	5.2
Amara Raja Batteries	20.7	19.4	17.3	20.1	21.2
Cholamandalam	19.4	18.9	19.0	18.0	16.6

एफआईआई/डीआईआई निवेश



सप्ताह का शेयर (जीएसके फार्मा)



बीएसई 500

मुनाफे में	Feb 1	Feb 7, 20	% chg
Schneider Electric Infra	78.15	107.45	37.49
Welspun Corp	166.85	223.85	34.16
Shilpa Medicare	294.20	386.30	31.31
Caplin Point Laboratories	283.05	365.35	29.08
Dishman Carbogen	71.55	91.15	27.39
Swan Energy	112.10	139.30	24.26
Shriram Transport Finance Co	987.00	1222.60	23.87
Honeywell Automation India	27975.75	34339.80	22.75
Shankara Building Products	368.20	450.35	22.31
Ajanta Pharma	1129.30	1369.10	21.23
L&T Finance Holdings	109.80	131.45	19.72
HEG	1027.85	1225.05	19.19
JM Financial	100.45	118.70	18.17
Godrej Properties	989.25	1168.65	18.13
Jindal Steel & Power	167.40	197.75	18.13
IIFL Finance	156.55	184.80	18.05
Aurobindo Pharma	467.05	546.65	17.04
Granules India	138.90	162.15	16.74
Info Edge India	2671.45	3090.85	15.70
MAS Financial Services	963.85	1115.05	15.69
Sun Pharma Advanced Research	177.25	204.90	15.60
Trent	573.85	662.70	15.48
Indiabulls Housing Finance	278.15	321.10	15.44
Bajaj Electricals	359.01	413.20	15.09
ITD Cementation India	57.95	66.60	14.93
GE Power India	679.20	780.40	14.90
Reliance Power	1.55	1.78	14.84
Abbott India	12321.35	14133.20	14.70
V-Mart Retail	1988.60	2277.15	14.51
JSW Steel	244.75	279.30	14.12
Adani Green Energy	186.35	212.30	13.93
Power Finance Corp	110.05	125.25	13.81
Force Motors	1212.20	1379.50	13.80
JB Chemicals & Pharmaceuticals	493.75	561.10	13.64
General Insurance Corp of Indi	239.60	272.20	13.61
Strides Pharma Science	438.55	497.90	13.53
Minda Corp	97.75	110.65	13.20

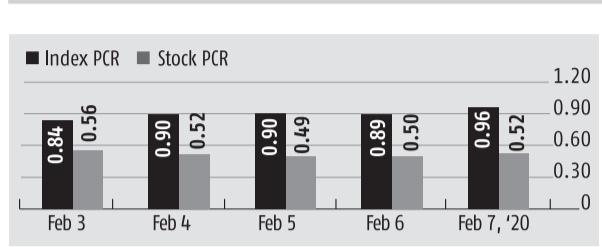
घाटे में

Gayatri Projects	51.35	39.85	-22.40
Jammu & Kashmir Bank	27.65	22.80	-17.54
GlaxoSmithKline Pharmaceutical	1637.90	1352.90	-17.40
Indiabulls Real Estate	101.65	91.25	-10.23
Manappuram Finance	184.25	166.95	-9.39
Gujarat Alkalies & Chemicals	392.65	358.60	-8.67
Dr Lal PathLabs	1769.40	1617.40	-8.59
Gateway Striparks	138.85	127.00	-8.53
Jain Irrigation Systems	7.51	6.93	-7.72
Suzlon Energy	2.48	2.29	-7.66
Aavas Financiers	1994.10	1843.40	-7.56
Rashtriya Chemicals & Fertilizers	49.75	46.55	-6.43
Deepak Fertilisers & Petrochem	103.90	97.30	-6.35
Indiabulls Integrated Services	116.30	109.05	-6.23
Venky's India	1641.90	1540.70	-6.16
Reliance Capital	8.73	8.21	-5.96
TeamLease Services	2528.15	2379.50	-5.88
Varroc Engineering	461.65	434.90	-5.79
KPR Mill	682.10	644.10	-5.57
Centrum Capital	22.80	21.55	-5.48
Arvind Fashions	377.05	356.85	-5.36
Sobha	428.90	405.95	-5.35
Dewan Housing Finance Corp	12.35	11.69	-5.34
Exide Industries	192.20	182.05	-5.28
PC Jeweller	21.80	20.65	-5.28
Indian Overseas Bank	10.25	9.73	-5.07
Chambal Fertilizers	171.55	163.40	-4.75
DB Corp	137.90	131.50	-4.64
V-Guard Industries	223.10	213.25	-4.42
Cera Sanitaryware	2643.05	2531.70	-4.21
Allahabad Bank	17.05	16.40	-3.81
Future Consumer	23.20	22.35	-3.66
Delta Corp	174.95	168.60	-3.63
Gujarat State Fertilizers	80.45	77.55	-3.60

निफ्टी स्नैपशॉट

	Feb 3	Feb 4	Feb 5	Feb 6	Feb 7, 19
Nifty 50 Spot	11707.9	11979.7	12089.2	12138.0	12098.3
Nifty 50 Future	11703.2	11964.3	12086.3	12136.4	12095.9
Prem/Discount	-4.8	-15.4	-2.9	-1.6	-2.4
Fut(Open Int)	14669	14662	14732	14750	14820
Fut(Contract)	188708	208921	148061	141374	91984
Fut(Value Rs Cr)	16537.8	18626.9	13354.8	12861.9	8345.3
PCR(Open Int)	0.8	1.1	1.2	1.2	1.2
PCR(Contract)	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
Major Call(Strike Price)	12000.0	12200.0	12100.0	12150.0	12500.0
Major Call(LTP)	5.1	4.0	30.0	0.9	13.6
Major Put(Strike Price)	12000.0	11800.0	12000.0	12100.0	12000.0
Major Put(LTP)	354.7	9.6	8.8	0.2	95.9

पुट/कॉल रेशियो



सेक्टर पर नजर

TOP GAINERS	OI '000	% chg	TOP GAINERS	OI '000	% chg
Textiles	1479	81.7	Auto Ancillaries	48030	24.0
Plantation & Plantation	639750	896250	Finance	344093	22.5
Products	26295	71.8	Healthcare	18132	20.1
Tyres	22100	69.4	Trading	37152	18.0
Fertilizers	5490	52.9	Paints/Varnish	19261	17.9
Cement	46685	50.3			
Miscellaneous	4628	45.8			
Leather	3248	36.5	Packaging	6601	-23.0
Entertainment	49706	29.7	Refineries	191962	-10.7
Construction	77760	26.5	Pharmaceutical	364	-7.9
Realty	54671	26.0	Logistics	6341	-0.2

कीमत में बढ़ोतरी के साथ ओपन इंटरस्ट

	Open Int as on Feb 1	Feb 7	% Chg	Price as on Feb 1	Feb 7	% Chg
Ambuja Cem	18707500	31827500	70.1	195.4	209.8	7.4
Chola Inv	4302500	6497500	51.0	318.6	340.0	6.7
SRF Ltd	639750	896250	40.1	3688.2	4109.9	11.4
United Brew	1645000	2224600	35.2	1279.8	1320.9	3.2
MRF	15800	21270	34.6	68686.6	70960.5	3.3
Century Tex	3263400	4337400	32.9	593.0	609.2	2.7
Rural Elect	20016000	26406000	31.9	139.5	155.1	11.2
Max India	7402200	5153200	-30.4	437.1	479.7	9.7
Tata Chem	2897100	3740400	29.1	740.7	763.8	3.1
Tata Global	11510100	14812200	28.7	372.7	396.7	6.5
IOC	73660000	54520000	-26.0	108.9	117.5	7.9
ACC	4080000	5024400	23.1	1426.6	1502.7	5.3
Biocon	11725400	14386500	22.7	287.3	308.9	7.5
Federal Bank	50540000	61558000	21.8	88.3	91.3	3.4
Escorts	3991900	4805900	20.4	773.8	867.9	12.2
Torrent Pwr	3756000	4503000	19.9	304.1	305.8	0.6
Balkrishna I	1184800	1416000	19.5	1049.0	1101.1	5.0
Marico	12729600	15154100	19.0	304.7	311.7	2.3

सेक्टर सूचकांक

Return (%)	Feb 7, '20	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
BSE Sensex	41,141.85	1.0	0.7	1.2	12.1	11.3
S&P CNX Nifty	12,098.35	1.1	0.4	0.7	11.4	9.3
BSE-100	12,245.44	1.3	1.0	1.1	11.7	8.6
BSE-200	5,114.39	1.5	1.6	1.7	12.7	9.6
BSE-500	15,866.56	1.4	2.0	2.3	13.1	9.4
CNX Midcap	18,367.50	2.0	7.9	9.4	17.1	9.0
CNX Nifty Junior	29,046.45	2.7	3.4	1.3	12.9	7.8
S&P CNX 500	10,000.75	1.4	2.0	2.4	12.9	9.3
BSE-Auto	18,076.79	-0.5	0.7	-2.1	18.0	-7.8
BSE-Bankex	35,675.44	1.1	-0.2	3.1	13.7	16.1
BSE-Cap. Goods	17,099.66	-2.1	0.1	-7.5	-0.5	-0.5
BSE-Cons Durable	27,090.41	3.6	10.2	8.7	21.7	23.9
BSE-FMCG	11,585.68	-0.5	2.2	-5.9	6.3	-1.5
BSE-Healthcare	14,282.78	2.3	6.2	7.3	13.6	1.5
BSE-IT Sector	16,124.14	1.6	3.0	4.2	3.1	2.6
BSE-TECK	8,084.42	2.2	4.4	7.2	5.6	4.5
BSE Realty	2,433.32	-3.7	7.1	14.7	21.9	39.1
BSE-Metal	10,003.48	5.4	-3.4	0.8	12.7	-5.9
BSE-Oil & Gas	14,309.32	2.8	-1.2	-7.3	13.4	3.0
BSE-PSU	6,682.99	1.8	-1.9	-5.8	2.5	-2.0

मोटा सौदा

Date	Stock	Client	Type	Quantity	Price (₹)
Feb 07	Aavas Financiers	Lake District Holdings	SELL	3660700	1,819.5
Feb 04	Manappuram Finance	Baring India Equity Fund	SELL	31095102	174.0
Feb 07	Aavas Financiers	Smallcap World Fund Inc	BUY	1534000	1,818.0
Feb 06	Asian Paints	Geetanjali Trading & Investments	SELL	1161300	1,860.0
Feb 06	Asian Paints	Sattva Holding & Trading	BUY	1161300	1,860.0
Feb 05	Westlife Development	Makino Holdings	SELL	4682533	425.1
Feb 04	Manappuram Finance	Baring India Equity Fund	SELL	10365034	174.0
Feb 05	Sp&ana Spoority Fin	Jm Financial India Trust	SELL	1600000	1,012.0
Feb 07	Aavas Financiers	Kotak FundsIndia Midcap Fund	BUY	887082	1,818.0
Feb 04	Indian Energy Exc	Lsvp Viii Mauritius	SELL	9098590	166.5
Feb 04	Manappuram Finance	Copthall Mauritius Investment	BUY	8650000	174.0
Feb 04	Manappuram Finance	Key Square Master Fund II Lp	BUY	8000000	174.0
Feb 05	Sp&ana Spoority Fin	Alberta Teachers Retirement	BUY	1316135	1,012.7
Feb 06	Indiabulls Hsg Fin	Credit Suisse Singapore	SELL	4021973	316.0
Feb 04	Manappuram Finance	Societe Generale	BUY	6000000	174.0
Feb 04	Indian Energy Exc	Nippon India Mutual Fund	BUY	5500000	166.5
Feb 07	Aavas Financiers	American Funds Insurance	BUY	402000	1,818.0
Feb 04	Motilal Oswal Financial	Passionate Investment Mgmt.	BUY	854273	773.0
Feb 05	Westlife Development	Sundaram Mutual Fund	BUY	1367100	425.0
Feb 04	Motilal Oswal Financial	Raamdeo Agrawal	SELL	626490	773.0
Feb 05	Westlife Development	Kuwait Investment Authority	BUY	896840	425.0
Feb 04	Indian Energy Exc	Nippon India Mutual Fund	BUY	2200000	166.5
Feb 04	Motilal Oswal Financial	Motilal Oswal	SELL	227783	773.0
Feb 03					

वाहन कर्ज देने वालों पर सकारात्मक होना जल्दबाजी

पुराने वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में तेजी से तीसरी तिमाही में मदद मिली लेकिन नए वाहनों की बिक्री कमजोर बनी हुई है और परिचालन की चुनौतियां आसान नहीं हुई हैं

हंसिनी कार्तिक

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के शेयर ने पिछले हफ्ते निवेशकों को चौंका दिया जब दिसंबर तिमाही के नतीजे पर प्रतिक्रिया जताते हुए शेयर ने 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। जबकि उसकी समकक्ष कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के शेयरों में तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद तेजी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का एक वर्ग यह सोचने के लिए विवश रह रहा है कि क्या वाहनों के लिए कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए स्थितियां अनुकूल हो गई हैं?

श्रीराम ट्रांसपोर्ट की तरफ से कर्ज वितरण में सालाना आधार पर 19 फीसदी की बढ़ोतरी भले ही हमें ऐसा मानने को प्रोत्साहित करे, लेकिन इसका विस्तृत ब्योरा व्यापक मानकों मसलन फंड की लागत, शुद्ध ब्याज मार्जिन (लेनदार के लाभ की माप करने वाला) और परिसंपत्ति गुणवत्ता में छुपा हुआ है। यह बताता है कि इन शेयरों पर पूरी तरह सकारात्मक बनने में अभी कसर रह गई है।

जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषकों ने एक नोट में कहा है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट का मार्जिन सालाना आधार पर 22 आधार अंक सिक्यूरिटी 7.6 फीसदी रह गया क्योंकि फंड की लागत 40 आधार अंक बढ़ गई, जिसकी वजह उच्च लागत वाली फंडिंग मसलन बैंक कर्ज और खुदरा जमाओं में हुई बढ़ोतरी है। महिंद्रा एंड



सुस्त रफ्तार

	कर्ज वितरण की रफ्तार (फीसदी)*	एनआईएम	बदलाव		
	क्यू-1 वि.व. 20	क्यू-2 वि.व. 20	क्यू-3 वि.व. 20	क्यू-3 वि.व. 20	आधार अंक
चोला फाइनेंस	22.0	7.0	-3.0	6.91	-10
एमएंडएम फाइनेंस	2.5	-10.0	-4.0	7.17	-21
श्रीराम ट्रांसपोर्ट	-8.4	-5.1	19.4	7.70	-31

* साल दर साल बदलाव, एनआईएम : शुद्ध ब्याज मार्जिन

स्रोत : ब्रोकरेज की रिपोर्ट

महिंद्रा फाइनेंस का शुद्ध ब्याज मार्जिन सालाना आधार पर 21 आधार अंक घटकर 7.17 फीसदी रह गया जबकि फंड की लागत में 8 आधार अंक की मामूली राहत मिली और यह 8.36 फीसदी पर पहुंच गया। यह मोटे तौर पर सिक्योरिटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट पर बढ़ते भरोसे की पृष्ठभूमि में हुई, कुल फंडिंग में जिसकी हिस्सेदारी तीसरी तिमाही में अब तक के सर्वोच्च स्तर 14.7 फीसदी पर पहुंच गई। अग्रिम पर फर्म का प्रतिफल हालांकि सालाना आधार पर 6 आधार अंक कम है, जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का संकेत दे रहा है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता की बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां सितंबर तिमाही के 8.7 फीसदी

के स्तर के करीब बनी रही, जिससे कुछ विश्लेषक यह मान रहे हैं कि कंपनी की परिसंपत्ति गुणवत्ता कमोबेश स्थिर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने हालांकि क्रमिक आधार पर इस आंकड़े में 60 आधार अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की, जिसके कारण एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विश्लेषक मान रहे हैं कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट चौंकाता है। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि चोला फाइनेंस और एमएंडएम फाइनेंस की तरफ

से तीसरी तिमाही में प्रावधान की लागत में बढ़ोतरी और बट्टे खाते में डालने का मामला क्रमशः 41.5 फीसदी और 78 फीसदी रहा। चोला की बात करें तो सकल एनपीए में क्रमिक आधार पर 10 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई और यह अनुपात 3.3 फीसदी रहा। इन लेनदारों के मामले में क्रेडिट की लागत का अनुमान सालाना आधार पर उच्च बना रहा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने यह 2.1-2.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया है जबकि चोला ने वित्त वर्ष 2020

में इसके एक फीसदी पर पहुंचने की संभावना जताई है, जो हाल के वर्षों में नहीं देखा गया है।

इन चिंताओं के बीच मंदी को मात देने में इन लेनदारों को जिनसे मदद मिल रही है वह है पुराने वाहनों के लिए कर्ज देने की उनकी क्षमता। विभिन्न वर्षों में इन कंपनियों ने जो ताकत हासिल की है वह विश्लेषकों को कर्ज की गुणवत्ता को लेकर कुछ भरोसा दे रहा है। लेकिन यहां भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के मजबूत कर्ज वितरण को छोड़कर बाकी कंपनियों के कर्ज वितरण में कमी जारी है, जो बताता है कि लेनदार बढ़त को लेकर सतर्क बने हुए हैं।

खास तौर से चोला फाइनेंस (जिसने तीसरी तिमाही तक ज्यादातर मानकों में अपनी समकक्ष को पीछे छोड़ दिया) के बारे में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों की उम्मीद है कि मध्यम अवधि में बढ़त की रफ्तार घटकर 15 फीसदी रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब तक आर्थिक माहौल में सुधार नहीं होता, चोला की उधारी की लागत में 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है।

इन फर्मों के मामले में एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है और वह है पुराने वाहनों के मामले में चूक की ज्यादा संभावना। एक देसी ब्रोकरेज के वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा, पुराने वाहनों के लिए कर्ज देना सुस्त बाजार के माहौल में बढ़त का एक मौका देता है। लेकिन ऐसे कर्ज के साथ शून्य रिकवरी जुड़ी होती है और पुनर्भूतान के लिए पूरी तरह से उधार लेने वालों के नकदी प्रवाह पर निर्भर होता है। अगर मंदी लंबे समय तक टिकती है तो ऐसे कर्ज की परिसंपत्ति गुणवत्ता कैसी रहेगी, इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है।

बाजार हलचल

कम लागत वाली पूंजी पर काम

एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने नई पूंजी जुटाने के लिए 4,000 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री शुरू की है। डीमार्ट खुदरा श्रृंखला की परिचालक को यह रकम जुटाने के लिए 3 फीसदी से थोड़ी कम हिस्सेदारी बेचनी होगी। तीन साल पहले कंपनी ने 1,870 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निगम में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी। तब से राधाकृष्ण दमानी प्रवर्तित इस कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब आठ गुना बढ़ा है। विशेषज्ञों ने कहा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे बढ़त के क्षमता के साथ अच्छी तरह प्रबंधित कंपनियां कम लागत वाली पूंजी का फायदा उठा सकती हैं। एक विश्लेषक ने कहा, एक ओर माहौल चुनौतीपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर उसके इर्द-गिर्द पर्याप्त नकदी है। उम्दा प्रदर्शन करने वाली कंपनियां सस्ती पूंजी तक पहुंच सकती हैं। यह शानदार चक्र है। एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन को छोड़ दें तो सूचीबद्धता के बाद पहली बार एवेन्यू सुपरमार्ट्स नए शेयर जारी कर रही है।

-समी मोडक

निवेशकों के रेडार पर आवास फाइनेंसर्स

जयपुर की आवास वित्त कंपनी आवास फाइनेंसर्स ने शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से अच्छा खासा निवेश देखा। तीन फंडों ने कुल मिलाकर 513 करोड़ रुपये का निवेश किया। स्मॉलकैप फंड ने सबसे ज्यादा 278 करोड़ रुपये का निवेश बीएसई पर बल्क डील के जरिए किया। उसके बाद कोटक मिडकैप फंड ने 161 करोड़ रुपये और अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस ने 73 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह निवेश आरबीआई की तरफ से वाणिज्यिक रिजल्ट एस्टेट के लिए फंसे कर्ज के नियमों में नरमी के एक दिन बाद देखने को मिला। एक साल में इस शेयर में 113 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विश्लेषक इस आवास वित्त कंपनी की परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर सकारात्मक हैं।

-जश कुपलानी

रेल पीएसयू में मुनाफावसूली

फंड मैनेजर चार रेल पीएसयू में मुनाफावसूली पर विचार कर रहे हैं, जिन्हें हाल के समय में सूचीबद्ध कराया गया है। आईआरसीटीसी, राइट्स, रेल विकास निगम और इस्कॉन इंटरनेशनल के शेयरों में आरंभिक सार्वजनिक निगम की कीमत के मुकाबले अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ज्यादातर आईपीओ में म्युचुअल फंडों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली है। एक फंड मैनेजर ने कहा, ऐसे ज्यादातर शेयरों में काफी क्षमता है, ऐसे में हम इन शेयरों में आई काफी तेजी के बाद एकीकरण की उम्मीद कर रहे हैं।

-जश कुपलानी

वित्तीय फर्मों : मूल कंपनी के मूल्यांकन में मजबूती की दरकार



श्रीपाद अंटे

कुछ समय पहले तक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईसीआईसीआई बैंक जैसे वित्तीय समूह का प्रमुख व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और बाजार भी उनकी सहायक कंपनियों पर सकारात्मक दिख रहा था। लेकिन कुछ बजट प्रस्तावों का इन कंपनियों की सहायक इकाइयों/अन्य व्यवसायों के आगामी प्रदर्शन के संदर्भ में नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन प्रस्तावों से कंपनियों को अपने पैतृक समूहों के शेयर मूल्यांकन में योगदान देने की अपनी क्षमता प्रभावित हो सकती है।

बजट की प्रमुख घोषणाओं में नई आयकर व्यवस्था के तहत आवास ऋण और बीमा प्रीमियम के संबंध में कर छूट समाप्त करना भी शामिल है। बीमा कंपनियों के लिए संभावित प्रभाव को देखते हुए कुछ विश्लेषकों ने सूचीबद्ध जीवन बीमा कंपनियों के संदर्भ में अपने कीमत लक्ष्य घटाने शुरू कर दिए हैं। ब्रोकरेज फर्मों के अनुमानों के अनुसार इससे प्रमुख वित्तीय कंपनियों के शेयर मूल्यांकन (बीमा व्यवसाय के योगदान) पर लगभग 14-16 प्रतिशत का प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि निवेशकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीमा कंपनियों पर दीर्घावधि प्रभाव की मात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, इन कंपनियों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को दुरुस्त बनाने के लिए भी कुछ समय तक काम करना होगा। उदाहरण के लिए, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के विश्लेषक नितिन अग्रवाल को नई कर व्यवस्था की वजह से बीमा कंपनियों की मूल कंपनियों के मूल्यांकन पर मामूली प्रभाव पड़ने का अनुमान है। अग्रवाल ने कहा, 'यदि ये ऋणदाता (पैतृक कंपनियों) लगातार मजबूत परिचालन प्रदर्शन दर्ज करने में सक्षम रहती हैं तो उनके मूल्यांकन को ताकत मिलेगी, भले ही उनके बीमा व्यवसायों में कुछ समस्याएं दिख रही हों।'

मजबूत वितरण फ्रैंचाइजी, दक्षता बढ़ाने की गुंजाइश, और कुल उधारी लागत में संभावित सुधार कुछ अन्य ऐसे कारक हैं जिनसे पता चलता है कि इन वित्तीय कंपनियों के प्रमुख व्यवसायों का प्रदर्शन मजबूत बना रहेगा। दरअसल, दिसंबर 2019 की तिमाही के नतीजों के बाद, बाजार मुख्य रूप से परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार की वजह से एसबीआई जैसे कॉरपोरेट बैंकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि वृद्धि की उम्मीदों को लेकर कुछ बदलाव जरूरी हो सकते हैं। प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के तहत, आवास ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर छूट भी समाप्त कर दी गई है जिससे ऋणदाताओं की खुदरा ऋण वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में विश्लेषक काजल गांधी के अनुसार, 'हालांकि 80सी कर छूट समाप्त किए जाने की वजह से घर खरीदारी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन इससे कर्ज लेकर घर खरीदारी का रुझान प्रभावित होगा, जबकि पहले यह बेहद आकर्षक बना हुआ था।' इससे स्थिति चिंताजनक हुई है, क्योंकि कई बैंक अपने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के विस्तार की कोशिश पहले ही शुरू कर चुके हैं। मार्च 2019 से, एक्सबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का योगदान दिसंबर 2019 तक उनकी कुल ऋण बुक में 300-400 आधार अंक तक बढ़कर 61-63 प्रतिशत हो गया। खुदरा आवास ऋणों का एचडीएफसी की ऋण बुक में 76 प्रतिशत का योगदान है। विश्लेषकों का कहना है कि उनकी शुल्क आय पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये ऋणदाता बीमा और अन्य निवेश उत्पादों की बिक्री से भी आय हासिल करते हैं। गांधी का मानना है कि इन वित्तीय सेवा प्रदाताओं का मजबूत प्रदर्शन इनके मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण होगा, भले ही अन्य व्यवसायों से योगदान में कमी आई हो।

बीएस बातचीत

वैश्विक निवेशक जारी रखेंगे भारत में निवेश

वित्त वर्ष 2021 का बजट पेश हो चुका है और भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा कर चुका है। जूलियस बेयर के मुख्य कार्याधिकारी आशिष गुमाश्ता ने पुनीत वाधवा को दिए साक्षात्कार में कहा कि बाजार का ध्यान फंडामेंटल (अर्थव्यवस्था व आय) के अलावा वैश्विक संकेतों खास तौर से कोरोनावायरस के डर और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर इसके संभावित असर की ओर वापस लौटेगा। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

बजट प्रस्तावों को आप कैसे देखते हैं?

इस साल के बजट में अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए बड़े सुधार और बढ़त को प्रोत्साहित करने वाले कुछ कदमों की उम्मीद की जा रही थी, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की सबसे खराब मंदी से दो-चार हो रहा है। हालांकि बजट इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कुल मिलाकर बजट में वित्तीय क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, रिजल्ट एस्टेट और निर्यात को लेकर बड़ी घोषणाओं का अभाव रहा, जो बढ़त को बहाल करने और कारोबारी धारणा के लिहाज से अहम है। बाजार जिस तरह से प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा था, वह नहीं मिला। अब बजट पूरा हो चुका है, लिहाजा शेयर बाजार फंडामेंटल (अर्थव्यवस्था व आय) के अलावा वैश्विक संकेतों खास तौर से कोरोनावायरस के जखिम और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर उसके संभावित असर की ओर वापस लौटेगा।

क्या अब आपको बाजार के एकीकृत होने की उम्मीद है?

हां। अल्पावधि में हमें इसके मौजूदा स्तर पर एकीकृत होने की उम्मीद है। हालांकि आर्थिक संकेतक अपना निचला स्तर छोड़ रहे हैं और यहां से धीरे-धीरे उभार आएगा। अपने इक्विटी निवेश को लेकर निवेशक इस बीच होने वाली गिरावट पर नजर रखेंगे। वैश्विक निवेशकों के लिए मुख्य चिंता कौन की है? मौजूदा मंदी के बावजूद वैश्विक निवेशक भारत में निवेश जारी रखेंगे और इस तरह से लंबी अवधि की बढ़त की क्षमता को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार में नरमी और अन्य एशियाई बाजारों की रफ्तार को लेकर संभावित जोखिम (कोरोनावायरस के प्रसार को देखते हुए) को देखते हुए भारत अपेक्षाकृत निवेश का आकर्षक गंतव्य बन सकता है। भारत को लेकर वैश्विक निवेशकों

की मुख्य चिंता आर्थिक रफ्तार में क्रमिक नरमी, आय में सुस्त सुधार और क्रेडिट का संकट है। उम्मीद है कि इन मौजूद पर सुधार होगा, ऐसे में वैश्विक निवेशक इन चीजों पर नजर बनाए रखेंगे।

भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों के मूल्यांकन को लेकर आप कितने सहज हैं?

बेंचमार्क सूचकांकों का मूल्यांकन मौजूदा स्तर पर (ऐतिहासिक मूल्यांकन के मुकाबले) उचित नजर आ सकता है। हालांकि यह व्यापक बाजारों का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि वहां सूचकांकों में शामिल कुछ दिग्गजों के हक में श्रुवीकरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त आय के चक्र में सुधार पीछे चला गया है, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में 5-6 फीसदी की सुस्त रफ्तार के तौर पर प्रतिबिंबित हुआ है।

मिडकैप और स्मॉलकैप क्षेत्र में निवेशकों को कैसे उतारना चाहिए?

लार्जकैप के मामले में निवेशक अपना मौजूदा आवंटन बनाए रख सकते हैं, खास तौर से उच्च गुणवत्ता व बढ़त वाले शेयरों में। हालांकि निवेशक मिडकैप में अपना आवंटन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। पिछले दो साल में मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों का मूल्यांकन घटा है, लेकिन अब वे अपने समकक्ष लार्जकैप के मुकाबले छूट पर कारोबार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर वैश्विक रफ्तार जारी रही तो ये शेयर साल 2020 में सुधरेंगे। मिडकैप व स्मॉलकैप

में हम निचले स्तर वाले शेयरों पर ध्यान देंगे, जहां कंपनी इस क्षेत्र की अग्रणी है या उनकी स्थिति उम्दा है और परिचालन के स्तर पर स्थिति अच्छी है। साथ ही वह शेयर कई साल के निचले स्तर या लंबी अवधि के औसत के मुकाबले काफी नीचे कारोबार कर रहा है।

अगले कुछ महीने में आर्थिक व भूराजनैतिक घटनाक्रम पर वैश्विक स्तर पर विभिन्न केंद्रीय बैंक किस तरह की प्रतिक्रिया जताएंगे?

आरबीआई के बारे में आपका क्या कहना है? वैश्विक स्तर पर कम बढ़ोतरी, कम महंगाई और केंद्रीय बैंकों के काफी उदार बने रहने की प्रवृत्ति 2020 में जारी रहने की संभावना है। अमेरिकी ट्रेजरी का प्रतिफल कोरोनावायरस के प्रसार के बाद घटा है और साल की दूसरी छमाही तक यह निचले स्तर पर बना रहेगा जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर ध्यान केंद्रित होगा और कोरोनावायरस का असर घट जाएगा। भारत में हम दरों के नरमी के चक्र की समाप्ति के करीब हैं, हालांकि नीतिगत रुख कुछ समय तक उदार बना रह सकता है।



प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले क्यों खास बनी हुई है रिटेलर डीमार्ट

विवेक सुजन पिंटो

देश में डीमार्ट के नाम से खुदरा श्रृंखला का परिचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स इस हफ्ते रकम जुटाने का दूसरा दौर शुरू करेगी। कंपनी ने पिछले हफ्ते पात्र संस्थागत नियोजन ((क्यूआईपी)) पेश किया था। क्यूआईपी के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने और गुरुवार को इस वजह से कंपनी का शेयर 52 हफ्ते के उच्चस्तर को छू जाने की खबर के बाद कंपनी सुविधियों में आ गई। डीमार्ट को देश के सबसे ज्यादा कुशल रिटेलरों में से एक माना जाता है, जिसका सकल व परिचालन मुनाफा मार्जिन क्रमशः 15 फीसदी और 8 फीसदी रहा। वहाँ समकक्ष कंपनियां मसलन स्पेंसर और फ्यूचर रिटेल का सकल मार्जिन 21-22 फीसदी के बीच है जबकि परिचालन मुनाफा मार्जिन 4 से 5 फीसदी है। यह जानकारी उनके वित्तीय नतीजे के आंकड़ों से मिली।

विशेषज्ञों ने कहा, सालाना आधार पर डीमार्ट की बिक्री प्रति वर्गफुट 37,045 रुपये रहा जबकि स्पेंसर का 17,139 रुपये और फ्यूचर का 13,166 रुपये। यह जानकारी ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल के विश्लेषकों अवि मेहता, पर्सी पंथाकी और कुणाल शाह ने दी। ऐसा तब है जबकि समीक्षाधीन अवधि में डीमार्ट के महज 176 स्टोर



थे, वहीं फ्यूचर के 1,511 और स्पेंसर के 156 आउटलेट थे। यह बताता है कि कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले खुदरा कारोबार क्षेत्र से ज्यादा हासिल कर रही है।

देश की सबसे बड़ी रिटेलर रिलायंस रिटेल यहाँ एकमात्र अपवाद है। विश्लेषकों ने कहा कि वित्त वर्ष 2019 में प्रति वर्गफुट बिक्री करीब 66,000 रुपये रही जबकि स्टोर की संख्या 10,415 थी। इसकी वजह यह है कि रिटेलर ने टियर-2, 3, और टियर-4 बाजार में प्रसार किया, पहुंच में सुधार किया और संगठित

प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कहां है डीमार्ट	डीमार्ट	रिलायंस रिटेल	फ्यूचर	स्पेंसर
बिक्री प्रति वर्गफुट	37,045 रुपये	65,776 रुपये	13,166 रुपये	17,139 रुपये
सेम स्टोर स्टोर में बिक्री की रफ्तार	17.80 फीसदी	उपलब्ध नहीं	6.80 फीसदी	3.10 फीसदी
संपत्ति टर्नओवर	3.5	3.7	3.7	3.7
पांच साल की बिक्री (सीएजीआर)	34 फीसदी	55 फीसदी	8.70 फीसदी	9.30 फीसदी

स्रोत : आईआईएफएल/कंपनी के नतीजे

खुदरा को छोटे शहरों तक ले गई। इसी रणनीति ने कंपनी को अपनी प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने में मदद की।

डीमार्ट के लिए सेम स्टोर बिक्री की रफ्तार समकक्ष कंपनियों से ज्यादा रही है। विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2019 में डीमार्ट का सेम स्टोर सेल 17.8 फीसदी और फ्यूचर का 3.1 फीसदी और स्पेंसर का 6.8 फीसदी। यह जानकारी इन कंपनियों के वित्तीय नतीजों से मिली। रिलायंस रिटेल के सेम स्टोर सेल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

एडलवाइस के कार्यकारी उपाध्यक्ष (शोध-संस्थागत इक्विटीज) अनवीश रॉय ने कहा, डीमार्ट अपने प्रॉडक्ट मिक्स में बदलाव कर रही है और अपने वेंडरों से कीमत पर दोबदारा बातचीत कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। उन्होंने कहा, फूड अभी भी डीमार्ट के राजस्व में 50 फीसदी है ज्यादा योगदान कर रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में रिटेलर ने आम इस्तेमाल वाले सामान व अपैरल में इजाफा किया है। इससे इस क्षेत्र से राजस्व हिस्सेदारी में सुधार हुआ है।

उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2019 में फूड ने राजस्व में 51.2 फीसदी योगदान किया जबकि आम इस्तेमाल की चीजों

का योगदान 28.3 फीसदी और गैर-खाद्य का 20.7 फीसदी रहा। दो साल पहले यानी वित्त वर्ष 2017 में फूड का योगदान 53.7 फीसदी था, आम इस्तेमाल की चीजों का 26.3 फीसदी और गैर-खाद्य का 20 फीसदी था।

ऑफलाइन व ऑनलाइन रिटेलरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच डीमार्ट ने आक्रामक छूट की नीति बनाए रखी है। कंपनी ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह क्यूआईपी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल और स्टोर खोलने व प्रतिस्पर्धा से जूझने में करेगी।

क्यूआईपी और ओएफएस से प्रवर्तक की हिस्सेदारी 80 फीसदी से घटकर 75 फीसदी रह जाएगी।

दूर की सोचकर ही करें कर बचाने को निवेश

कर बचाने की योजनाएं चुनते समय संपत्ति आवंटन, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश की अवधि का जरूर रखें खयाल

संजय कुमार सिंह

अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके दफ्तर के अकाउंट विभाग से आपके पास मेल आ गया होगा, जिसमें आपसे चालू वित्त वर्ष के दौरान कर बचाने के लिए किए गए निवेश के सबूत मांगे गए होंगे। वास्तव में आपको कर बचाने के लिए निवेश का काम चालू वित्त वर्ष के आरंभ यानी पिछले साल अप्रैल से ही शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसा करने से चूक गए तो भी बहुत देर नहीं हुई है। हां, कर बचाने वाली योजनाएं चुनते समय अब आपको दिमागी मशक्कत जमकर करनी होगी या वित्तीय सलाहकार की मदद लेनी होगी। बीमा एजेंट और बैंक रिलेशनशिप मैनेजर भी आखिरी के तीन महीनों यानी जनवरी से मार्च के बीच बिक्री बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। यही वजह है कि इन महीनों में आपके पास बैंक और बीमा कंपनियों से एक के बाद एक फोन आते रहते हैं। यहां भी आपको झंझों में फंसने से बचना होगा। हो सकता है कि वे आपको जो योजना बेच रहे हैं, उसमें उन्हें तो तगड़ा कमीशन मिल रहा है मगर योजना आपके लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए निवेश का फैसला करते समय सावधान रहें। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेश का मूल मंत्र यही है कि कर बचाने के लिए किया जा रहा निवेश व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्य के मुताबिक ही हो। क्लियरटेक्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्य अधिकारी अर्चित गुप्ता कहते हैं, 'सबसे पहले व्यक्ति को अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्य तय करने चाहिए। लक्ष्य तय हो जाएं तो अपनी जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कर बचाने के मकसद से निवेश करना चाहिए।'



संपत्ति आवंटन से तय हो निवेश

अपने मौजूदा निवेश पोर्टफोलियो में संपत्ति आवंटन पर नजर दौड़ाए और देखिए कि कुछ कमी तो नहीं है। सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार और फिनस्कॉलर्ज वेल्थ मैनेजर की सह-संस्थापक एवं प्रिंसिपल एडवाइजर रेणु माहेश्वरी कहती हैं, 'यदि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का अनुपात कम रह गया है तो इक्विटी लिंकड सेविंग्स स्कीम

(ईएलएसएस) जैसी योजना पर विचार कीजिए।' लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में डेट का अनुपात कम रह गया है तो आप स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) का दामन थाम सकते हैं। आप अपना समूचा मूल वेतन और महंगाई भत्ता इसमें डाल सकते हैं। इसमें जमा रकम पर वही ब्याज मिलता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर मिलता

है। चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज की दर 8.65 फीसदी तय की गई है। डेट के मामले में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) भी अच्छा विकल्प है, जिसमें फिलहाल 7.9 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिक सरकारी गारंटी वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश कर सकते हैं, जिस पर 8.6 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

बीमा की जरूरत टटोलें

सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर भी परिवार के वित्तीय लक्ष्यों या जीवनशैली पर कोई फर्क नहीं पड़े। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जीवन बीमा खरीदना जरूरी है। जिस पर भी परिवार के लोग मसलन माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या बच्चे आश्रित हैं या जिस पर आवास ऋण, वाहन ऋण जैसी देनदारियां हैं, उसे अपने परिवार को महफूज रखने के लिए अपना टर्म बीमा जरूर करा लेना चाहिए। इसके लिए ह्यमन लाइफ वेल्थ कैलकुलेटर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उनका इस्तेमाल कीजिए और पता कीजिए कि आपको कितनी राशि का जीवन बीमा चाहिए। आप इसके लिए वित्तीय सलाहकार की मदद भी ले सकते हैं। बीमा प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। लेकिन बीमा की जरूरत पूरी करने के लिए इंश्योरेंस-कम-इन्वेस्टमेंट प्लान कभी मत खरीदिए क्योंकि उनमें आपको काफी कम बीमा कवरेज मिलता है। इसके बाद देखिए कि आपके पास इतना स्वास्थ्य बीमा है या नहीं कि आपके परिवारों के अस्पताल में भर्ती होने पर आपके ऊपर बोझ नहीं आए। महानगरों में एकल परिवार के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का फैमिली फ्लोटर बीमा जरूरी है। छोटे शहरों में 5 लाख रुपये के बीमा से भी काम चल सकता है। सेबी में पंजीकृत वित्तीय सलाहकार पर्सनलफाइनेंसप्लान डॉट इन के संस्थापक दीपेश राघव समझाते हैं, 'जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर धारा 80डी के तहत 25,000 रुपये तक की छूट मिल जाती है। यदि आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम अदा कर रहे हैं तो आप कुल 75,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।'



इंश्योरेंस-कम-इन्वेस्टमेंट कभी नहीं

कई करदाता आयकर बचाने के लिहाज से निवेश करने के लिए आखिरी मोंके तक का इंतजार करते हैं। जब आफत सिर पर आ जाती है तो वे किसी भी बीमा एजेंट के पास पहुंच जाते हैं। उस सूरत में अक्सर उनके हाथ में पारंपरिक बीमा योजना पकड़ा दी जाती है जैसे मनीबैक, आजीवन बीमा या एनडाउमेंट प्लान। इन योजनाओं में कई दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत तो यही है कि उनमें बीमा शामिल होता है। राघव कहते हैं, 'यदि आपके पास पहले से ही पर्याप्त बीमा है या आपको बीमा की जरूरत ही नहीं है तो आप बेवजह ही इन योजनाओं पर मॉर्टलिटि शुल्क चुकाते रहेंगे। जिनकी उम्र ज्यादा होती है, उनके लिए मॉर्टलिटि शुल्क भी ज्यादा ही होता है।' आप जो भी प्रीमियम अदा करते हैं, उसका एक हिस्सा मॉर्टलिटि शुल्कों में चला जाता है और इन योजनाओं से प्रतिफल कम हो जाता है। इतना ही नहीं इस तरह की योजनाएं ज्यादातर बॉन्ड में निवेश करती हैं। इन्होंने वजहों से उन पर 4-5 फीसदी से ज्यादा प्रतिफल नहीं मिल पाता। माहेश्वरी कहते हैं, 'यदि आप दीर्घकालिक नजरिये से, मान लीजिए 25-30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको ऐसी इक्विटी योजना में रकम लगानी चाहिए, जो आपको दो अंकों में प्रतिफल दे सके। इंश्योरेंस-कम-इन्वेस्टमेंट योजनाओं में प्रतिफल कम रहता है। आपके निवेश से ही तय होगा कि सेवानिवृत्ति के समय आप भरे-पूरे रहेंगे या तंगहाल रहेंगे।' लेकिन ऐसी योजनाओं से बाहर निकलना महंगा हो सकता है।

जोखिम के हिसाब से करें निवेश

यदि आपके भीतर निवेश के मामले में ज्यादा उतारचढ़ाव झेलने की कुव्वत नहीं है तो आपको डेट या हाइब्रिड योजनाओं में ही रकम लगानी चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) आपके लिए युफीद हो सकती है क्योंकि वह निवेशकों को इक्विटी और डेट के विभिन्न स्तर चुनने की आजादी देती है। गुप्ता कहते हैं, 'जो सेवानिवृत्ति के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं और इक्विटी में रकम लगाना चाहते हैं, वे एनपीएस चुन सकते हैं।' माहेश्वरी भी एनपीएस में ही निवेश करने की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट मिल जाती है।



निवेश और नकदी की जरूरत खंगालें

कर बचाने के फेर में निवेश करते समय ध्यान रखें कि यह निवेश की आपकी पूरी योजना के अनुरूप हो। यदि आपके पास सात साल या अधिक समय है तो आप ईएलएसएस जैसी पूरी तरह इक्विटी योजना में रकम लगा सकते हैं। निवेश की अवधि बढ़ी हो तो कुछ समय का उतारचढ़ाव झेलने और अच्छा प्रतिफल हासिल करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इन योजनाओं में लगाई जा रही रकम की आपको जरूरत कब होगी। मिसाल के तौर पर यदि आपको कुछ अरसे बाद ही रकम की जरूरत है तो यूनिट लिंकड इन्वेस्टमेंट प्लान (यूएलपी) में निवेश करना समझदारी नहीं होगी। यूएलपी में आपके रकम से कम पांच साल के लिए फंस जाती है यानी आप उसमें से पांच साल बाद ही रकम निकाल सकते हैं। ईपीएफ या वीपीएफ और पीपीएफ भी लंबे समय की निवेश योजनाएं हैं और उनमें तरलता की कमी होती है यानी उनमें से आसानी से रकम निकाली नहीं जा सकती इसलिए यदि आपको बीच में रकम की जरूरत पड़ती है तो इनसे बहुत कम धन निकाल पाएंगे। ईपीएफ और वीपीएफ में कुछ खास स्थितियों में ही - गंभीर बीमारी में या बच्चों की शिक्षा या शादी आदि के लिए - धन निकाला जा सकता है। ईएलएसएस में सबसे कम केवल तीन साल की लॉक-इन अवधि है।



बजट संदेश : संपत्ति बढ़ाने को करें निवेश

संजय कुमार सिंह और बिंदिश सांरंग

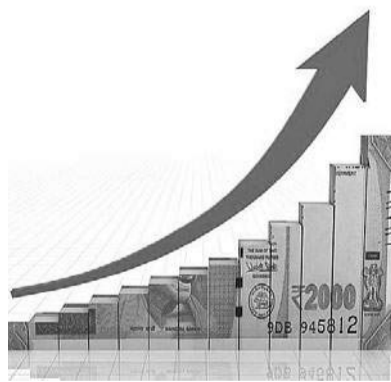
बजट के बाद बहुत से निवेशक नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे, जिसके तहत उन्हें कर बचाने के लिए कोई निवेश नहीं करने की जरूरत होगी। ऐसे में निवेशकों को कर बचत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय योजनाएं चुनने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें उन निवेश योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, जो उनकी संपत्ति में ज्यादा से ज्यादा इजाजा करें। अब निवेशक बेहतर विकल्प चुन पाएंगे। मुंबई के कर एवं निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा, 'जब आप निवेश का फैसला कर की बचत को ध्यान में रखते हुए लेते हैं तो आपकी पर्सद में पूर्वग्रह होता है और आप सबसे बेहतर निवेश नहीं कर पाते हैं।'

भ्रामक बिक्री में कमी

नई कर व्यवस्था का एक स्पष्ट फायदा यह होगा कि जनवरी से मार्च तक के कर बचाने के सीजन में वित्तीय योजनाओं की भ्रामक बिक्री में कमी आएगी। बहुत से निवेशकों को बीमा एवं निवेश योजनाएं केवल इसलिए बेच दी जाती थी क्योंकि इनसे कर बचता था। इन योजनाओं में बीमा कवर आम तौर पर अपर्याप्त होता था। ये योजनाएं मुख्य रूप से निश्चित आमदनी वाली योजनाओं में निवेश करती हैं, इसलिए उन पर सालाना प्रतिफल 4-5 फीसदी से अधिक नहीं होता है। इन योजनाओं से बाहर निकलना भी महंगा पड़ता था।

लॉक इन से बचें

कर बचत योजनाओं में निवेश नहीं करने का एक फायदा मिलेगा कि निवेशक ऐसी योजनाओं में निवेश कर सकेंगे, जिनमें कोई लॉक इन नहीं होता है। प्लूटस कैपिटल में प्रबंध सल्लाहदार अंकुर कपूर ने कहा, 'पहले एक अत्यधिक पुरातनपंथी निवेशक पांच वर्षीय कर बचत वाली सार्वधि जमा में निवेश करता था। अब वह किसी भी सामान्य सार्वधि जमा या आवर्ती जमा में पैसे लगाने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनमें सबसे बेहतर प्रतिफल मिलता है।' सेवानिवृत्त



■ कर बचाने वाली बहुत सी वित्तीय योजनाएं ऐसी भी हैं, जिनके लिए आप कर लाभ नहीं भी लेते हैं तो वे आपके लिए उपयोगी साबित होंगी

कर्मचारी जैसी बहुत सी श्रेणियों के निवेशक भी कर बचाने वाली योजनाओं में निवेश करते हैं ताकि उनकी कर देनदारी कम हो, भले ही वित्तीय योजना के नजरिये से इस निवेश का बहुत ज्यादा तुक नहीं हो।

फैसलों पर कर की फिक्र हावी

कई बार वित्तीय फैसलों पर केवल कर की फिक्र हावी होती है। प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स में मुख्य वित्तीय योजनाकार विशाल धवन ने कहा, 'बहुत से लोग जिन्होंने आवास ऋण लिया हुआ है, वे कर छूट हासिल करने के लिए अतिरिक्त पैसा होने के बावजूद पूर्व भुगतान नहीं करते हैं।' लेकिन जब वे पूर्व भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें ऋणदाता को ज्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। धवन ने कहा, 'जिन लोगों ने नई कर व्यवस्था को चुना है, वे अब पूर्व भुगतान कर सकेंगे।'

इसी तरह आम तौर पर लोग इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) चुनते हैं क्योंकि उनमें इक्विटी प्रतिफल भी शामिल होती है और उनमें कर बचत भी होती है। लेकिन वे प्रतिफल के मामले में सबसे बेहतर नहीं हैं। अब निवेशक

कोई भी ऐसा अच्छा डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड चुन सकेगा, जो उसके पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त है।

बचत का लाभ छिन जाएगा

कर बचाने के लिए निवेश की अनिवार्यता का यह फायदा होता है कि इससे बाध्यता की वजह से बचत होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है, जो अभी शुरुआती करियर में हैं। अब बचत और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश का फैसला पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर होगा। कर व्यवस्था उसे निवेश के लिए प्रेरित नहीं करेगी। जो लोग नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे, उन्हें हाथ में आने वाले वेतन का कम से कम 30 फीसदी बचाने और निवेश का लक्ष्य तय करना चाहिए।

कर बचाने वाली योजनाएं

ऐसी बहुत सी योजनाएं, जिन पर कर लाभ मिलता है, वे नई कर व्यवस्था में भी प्रासंगिक हैं। लोगों को उनकी खरीद केवल इसलिए नहीं रोक देनी चाहिए कि उन्हें उनके कर लाभ की जरूरत नहीं है। टर्म इंश्योरेंस पर धारा 80 सी के तहत लाभ मिलता है, लेकिन इसे अब भी खरीदा जाना चाहिए। हर परिवार को 5-10 लाख रुपये का फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदा जाने चाहिए, भले ही वह धारा 80डी का लाभ नहीं ले रहा हो। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भी अच्छा विकल्प है, जिस पर धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलता है। यह कम लागत की योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए आपकी बचतों को लॉक करती है ताकि इसे दूसरी जरूरतों में खर्च नहीं किया जाए।

फिनसेफ के संस्थापक निदेशक मरिन अग्रवाल कहते हैं, 'निवेश उत्पादों को इस आधार पर चुना जाना चाहिए कि वे आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करते हैं या नहीं। अगर आप नई कर प्रणाली भी चुनते हैं तो इक्विटी एवं डेट म्यूचुअल फंडों, सार्वजनिक भविष्य निधि और स्वैच्छिक भविष्य निधि में निवेश जारी रखें।'

कर्जदारों के लिए बेहतर बेंचमार्क दर

आपको केवल प्रशासनिक और कानूनी कामों के लिए ही खर्च करना होगा

जयदीप घोष और बिंदिश सांरंग

अगर आपने आवास ऋण लिया है या आप सूअर, छोटे या मझोले आकार का कोई उद्यम चलाने के लिए कर्ज ले चुके हैं तो आपके पास अब एक नया विकल्प आ गया है। यह विकल्प है बाहरी बेंचमार्क से जुड़े कर्ज का।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में कहा था कि फ्लोटिंग दर वाले सभी ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना ही पड़ेगा। कर्ज मांगने वालों को अब इसी तरह की दरें मिलेंगी। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जनवरी से अपनी बाहरी बेंचमार्क दर में 25 आधार अंक की कटौती कर दी। सोमवार से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से जोड़ने के विकल्प पर अब विचार कर सकते हैं। यह अच्छा विकल्प इसलिए भी होगा कि पहले से चली आ रही बेंचमार्क मसलन कोष की सीमांत लागत पर आधारित उधारी (एमसीएलआर) या उससे भी पुरानी आधार दर (बीपीएलआर) के मुकाबले बाहरी बेंचमार्क अधिक पारदर्शी है।

आरबीआई ने बाहरी बेंचमार्क से ब्याज दर जोड़ने का दबाव डालकर बहुत अच्छा किया क्योंकि



एमसीएलआर की समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 2017 में गठित जनक राज समिति ने पाया था कि चार शीर्ष बैंकों के 30 फीसदी से भी अधिक ग्राहक एमसीएलआर से नहीं जुड़े हैं, जबकि उसे लागू हुए 18 महीने गुजर चुके थे। खराब बात यह थी कि कई ग्राहक उस बन्त भी आधार दर या वीपीएलआर से ही जुड़े हुए थे। इससे साफ हो गया कि लंबी अवधि के लिए कर्ज लेने के बाद ग्राहक नए घटनाक्रम या बदलावों की खबर लेना बंद कर देते हैं या अक्सर आलस की वजह से कोई बदलाव नहीं करते।

प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के संस्थापक तथा मुख्य कार्य अधिकारी विशाल धवन कहते हैं, 'हमारी सलाह यही है कि बाहरी बेंचमार्क दर से अपना कर्ज जोड़ लिया जाए। भारत में दरों में कटौती से जुड़ी एक बड़ी चुनौती हमेशा रही है, जो बैंकों की ओर से आती

है। बैंक पहले ही कर्ज ले चुके ग्राहकों को दर कटौती का फायदा बहुत देर में या बहुत कम देते हैं। रिजर्व बैंक ने यही देखकर बाहरी बेंचमार्क दर से कर्ज जोड़ने का दबाव डाला। हमें लगता है कि अब भी आधार दर या एमसीएलआर उधारी प्रणाली से ही जुड़े हुए ग्राहकों को बाहरी बेंचमार्क का रास्ता चुनना चाहिए।

विवेकतार संस्थापक स्विनल केंधे की सलाह भी कमोबेश ऐसी ही है। वह कहते हैं, 'जैसे ही बेहतर दर का मौका मिले, उसे दोनों हाथों से लपक लें। चाहे तो उसके लिए दूसरी ऋणदाता संस्था के पास जाएं या मौजूदा ऋणदाता से ही मोलभाव करें।'

फिलहाल ज्यादातर बैंकों ने रीपो दर का बाहरी बेंचमार्क के तौर पर चुना है। कर्ज लेने वालों को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों से नियमित रूप से रीपो दर का पता चलता रहता

है, इसलिए इसमें काफी पारदर्शिता होती है। कई दूसरे फायदे भी हैं। मिसाल के लिए बैंक किसी भी कर्ज का स्प्रेड तय करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन वह क्रेडिट-रिस्क प्रीमियम तभी बदल सकता है, जब उधार लेने वाले के क्रेडिट में बहुत अधिक बदलाव होता है। लागत से जुड़े दूसरे घटक जैसे परिचालन लागत या खर्च भी तीन साल में केवल एक बार ही बदलते हैं। चूंकि दरों में बदलाव तीन महीने में एक ही बार होता है, इसलिए मासिक किस्तों में भी बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की आशंका नहीं होती।

बाहरी बेंचमार्क से जुड़ने की प्रक्रिया भी मुश्किल नहीं है। जो भी मौजूदा कर्जदार पहले ही भुगतान कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी खर्च किए बिना ही बेंचमार्क से जुड़ी दर अपनाने का मौका मिल जाएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक उन्हें केवल वाजिब प्रशासनिक और कानूनी खर्च चुकाने होंगे।

धवन बताते हैं, 'खर्च हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि ग्राहक अपनी पुरानी ऋणदाता कंपनी के साथ रहकर ही नई दर प्रणाली चुन रहा है या नहीं। इसमें अतिरिक्त खर्च भी होता है। बेहतर है कि आप बाजार में उतरें और दूसरे विकल्प भी तलाशें।'

मगर यह भी ध्यान रखें कि अगर आपका कर्ज अगले दो साल में पूरी चुक जाने वाला है तो बाहरी बेंचमार्क को अपना फिजूल ही होगा। हां, अगर आपको कर्ज लिए हुए अभी दो-तीन साल ही हुए हैं तो इसे आजमाया जा सकता है।

कोरोनावायरस: मास्क निर्यात पर हटाई रोक

केंद्र सरकार ने पिछले महीने यह वायरस फैलने के बाद मास्क और दस्तानों के निर्यात पर लगाया था प्रतिबंध

सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने पिछले महीने चीन में कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने के बाद कपड़े और दस्ताने समेत व्यक्तिगत बचाव के सभी उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम इस लिहाज से प्रासंगिक था कि कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए इन चीजों की मांग बढ़ने का अंदाजा था। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘सर्जिकल मास्क, एक बार इस्तेमाल कर छोड़ दिए जाने वाले मास्क तथा एनबीआर ग्लवज को छोड़ सभी दस्तानों के निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अन्य संरक्षण उपकरणों के निर्यात पर रोक लगी रहेगी।

मोदी ने की मदद की पेशकश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखकर कोरोनावायरस के प्रकोप से निपटने में भारत की ओर से मदद की पेशकश की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पत्र में प्रधानमंत्री ने चीन में वायरस के प्रकोप के खिलाफ चीनी राष्ट्रपति और वहां के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। सूत्रों ने बताया कि चिनफिंग को भेजे पत्र में मोदी ने इस चुनौती से निपटने के लिए चीन को भारत की ओर से मदद की पेशकश की और साथ ही इस वायरस से लोगों की मौत पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने हुबेई प्रांत से करीब 650 भारतीयों को निकालने में मदद देने के लिए चिनफिंग के प्रति आभार भी जताया।

केरल में ब्रेथलाइजर टेस्ट रोका

विमानन नियामक नागरिक उड्डन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोनावायरस की वजह से अगले 15 दिनों के लिए केरल के चार हवाई अड्डों पर विमानन कर्मचारियों के लिए उड़ान से पहले श्वास परीक्षण (ब्रेथलाइजर टेस्ट) बंद कर दिया है। ब्रेथलाइजर टेस्ट यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने श्वास पी हुई है या नहीं।

डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि केरल के चार हवाई अड्डों- कालीकट, कन्नूर, त्रिवेंद्रम और कोचीन से रवाना होने वाली उड़ानों के कर्मचारियों को उड़ान के अन्य शहर में उतरने के बाद अनिवार्य



कोलकाता में अस्पताल के बाहर कोरोनावायरस के बारे में जागरूकता के लिए लगा बोर्ड पीटीआई

रूप से परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। देश में अभी तक कोरोनावायरस के तीन मामले सामने आए हैं। ये सभी केरल के हैं। भारत में इस बीमारी से संक्रमित पाए गए सभी लोग छात्र हैं, जो हाल में चीन के वुहान शहर से लौटे थे।

अधर में एयरशो

इस बीच, सिंगापुर एयरशो के आयोजक इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि प्रदर्शकों ने कोरोनावायरस की चिंताओं के कारण खुद को एशिया के इस सबसे बड़े एयरशो से दूर कर लिया है। यह हवाई शो ऐसे समय हो रहा है, जब दुनियाभर में स्वास्थ्य और आर्थिक चिंताएं बनी हुई हैं। हर दो साल में होने वाले इस आयोजन में कुछेक सौदे ही होने के आसार हैं। इस आयोजन में स्वास्थ्य चेतावनियों के कारण नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इससे विमानन कंपनियों के लाभ और विमानों की मांग पर आशंका के बादल छा गए हैं। यह शो 11 से 16 फरवरी तक चलेगा। *एजेंसिया*

कारोबारी जगत के सर्वश्रेष्ठ सात...

निर्णायक मंडल ने कारोबारी प्रशासन, समाज में योगदान, नेतृत्व और नवाचार पर दिया ज्यादा जोर

पृष्ठ 1 का शेष

निर्णायक मंडल के अध्यक्ष बिड़ला ने चर्चा शुरू करते हुए सदस्यों से पूछा कि सूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम पर किसी को एतराज है तो बताएं। दो सदस्यों ने स्वयं से संबंधित श्रेणियों में विचार-विमर्श से खुद को दूर रखा। मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष के बिज़नेस स्टैंडर्ड रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर चुने गए नामों की सूची निर्णायकों के पास पहले ही पहुंच गई थी। इन्हीं में से ‘सीईओ ऑफ द इयर’ चुना जाना था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय फर्मा और लघु एवं मझोले उपक्रमों की श्रेणियों में विजेताओं के नाम भी इसी सूची से चुनने थे।

निर्णायक मंडल की चर्चा में कारोबारी प्रशासन, समाज के प्रति योगदान, स्तर, निरंतरता, नेतृत्व और नवाचार पर ज्यादा जोर दिया गया। बिड़ला ने कहा कि विजेताओं के चयन के दौरान वित्तीय आंकड़ों के अलावा कंपनियों द्वारा कारोबार संचालन के उच्च मानदंड का पालन किए जाने और समाज को कुछ लौटाने की बात ध्यान में रखनी चाहिए।

2017 में बीएस अवॉर्ड जीतने वाले जिंदल की राय थी कि विजेता का चयन करते समय बाजार पूंजीकरण में वृद्धि ही नहीं बल्कि कंपनी के समग्र विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। टोक्यो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए काका ने वैश्विक दृष्टिकोण से प्रत्येक कंपनी के बारे में अपनी राय दी।

अंततः टाइटन कंपनी को टाटा समूह की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाने में योगदान के लिए भट्ट को सीईओ ऑफ द इयर के सम्मान से नवाजा गया। निर्णायक मंडल की पंसद पर श्राॅफ ने कहा, ‘भट्ट ने मोर्चे पर रहकर कंपनी का नेतृत्व किया और आज टाइटन जहां खड़ी है, उसमें उनका अहम योगदान है।’

सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई क्योंकि पहली नजर में वित्तीय अनुपात महत्त्वपूर्ण था, लेकिन नवाचार पर ध्यान देने और कमजोर मांग के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में संस्थान को खड़ा करने की उपलब्धि को भी समान महत्त्व दिया गया। सूचीबद्ध कंपनियों के आंकड़ों के अलावा

निर्णायक मंडल के सदस्यों ने कंपनी, उद्योग और कारोबारी माहौल को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर भी चर्चा की।

बिड़ला ने कहा, ‘निर्णायक मंडल के सदस्यों ने साल के विजेता के चयन में विचार-विमर्श पर अधिक समय खर्च किया। फैसला मुश्किल था क्योंकि सूची में कई अच्छी कंपनियां थीं।बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर सभी छांटी गई कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन शानदार दिख रहा था।’

निर्णायक मंडल ने एलएॅंडटी को कंपनी ऑफ द इयर चुना और इंद्रप्रस्थ गैस ने स्टार पीएसयू ऑफ द इयर का खिताब जीता।नेस्ले को स्टार एमएनसी ऑफ द इयर और विनती ऑर्गेनिक्स को स्टार एसएमई ऑफ द इयर घोषित किया गया।किराना सामान की आपूर्ति करने वाली कंपनी बिगबास्केट को स्टार्टअप ऑफ द इयर चुना गया।

इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कई नामों पर विचार-विमर्श किया गया लेकिन निर्णायक मंडल ने चुने गए नामों के कारोबारी मॉडल पर भरोसा जताया। नैयर ने कहा, ‘ऐसे साल में हम इस तरह की कंपनी इस साल की तरह हम ऐसी कंपनी चाहते थे जिसका अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान रहा हो और जिसने रोजगार सृजन के साथ ही निर्यात आय में भी बेहतर प्रदर्शन किया हो। इन मानदंडों पर एलएॅंडटी से बेहतर और कोई कंपनी नहीं हो सकती।’

भारत के कारोबारी जगत में गहरी छाप छोड़ने वाली कई हस्तियों पर भी निर्णायक मंडल में विचार-विमर्श किया गया लेकिन सभी ने सॉफ्टवेयर दिग्गज विप्रो के संस्थापक चैयरमैन अजीम प्रेमजी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के लिए चुनने पर मुहर लगा दी।

बिड़ला ने कहा, ‘विप्रो की सफलता की जबदस्त कहानी रही है, लेकिन प्रेमजी ने अपने परोपकार के जरिये जिस तरह का प्रभाव डाला है, उसे देखते हुए यह सम्मान

उन्हों के हिस्से आया। प्रेमजी कंपनी संचालन के ऊंचे पैमाने गढ़ने और उन पर चलने के लिए जाने जाते हैं। यह बात भी उनके पक्ष में गई। इन सभी वजहों से प्रेमजी लाइफटाइम अचीवमेंट श्रेणी में अन्य प्रतिभागियों पर भारी पड़े।’

निर्णायक मंडल की नजर में प्रेमजी कारोबार की दुनिया की बड़ी शक्ति्सयत तो हैं ही, बड़े लोकोपकारी भी हैं। उनके नेतृत्व में विप्रो निरंतरता के साथ आगे बढ़ी है। फरवरी 2020 तक विप्रो का बाजार मूल्यांकन करीब 1.39 लाख करोड़ रुपये था और यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में एक है।

प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने का दृढ़ निश्चय प्रेमजी की निजी जिंदगी में भी झलकता है। जब उनके पिता का निधन हुआ तो परिवार का खाद्य तेल कारोबार संभालने के लिए 1966 में उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़कर स्टैनफर्ड से वापस आना पड़ा था। 30 साल बाद वह स्टैनफर्ड लौटे और अधूरी पढ़ाई पूरी कर डिग्री हासिल की।

परोपकारी के तौर पर प्रेमजी देश में बाकी सभी उद्योगपतियों से ऊपर रहे हैं। भारत में शिक्षा के लिए धन मुहैया करने के मकसद से उन्होंने विप्रो के 12.5 करोड़ डॉलर के शेयर 2001 में एक न्यास को दान दे दिए। यह दान भारत में आज की तारीख तक सबसे बड़ा दान है। इसी तरह नौ साल बाद एक

बार फिर प्रेमजी ने विप्रो के 2 अरब डॉलर के शेयर उसी न्यास को दे दिए। फरवरी 2013 में उन्होंने कंपनी में अपनी 12

फीसदी हिस्सेदारी (उस समय कीमत करीब 2.2 अरब डॉलर) उस न्यास के नाम कर दी। फाउंडेशन के पास इस समय विप्रो के 18 फीसदी शेयर हैं। 2019 में 7.6 अरब डॉलर का दान देकर प्रेमजी उस वर्ष लोक कल्याण के लिए सबसे अधिक दान देने वाले बन गए। प्रेमजी का कुल दान 2019 तक बढ़कर 21 अरब डॉलर हो गया।

‘स्टार्टअप ऑफ द इयर अवार्ड’ के

चीन में मरने वालों की संख्या 811 हुई

चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 811 हो गई है और इसके संक्रमण के 37,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि शनिवार को इससे 89 और लोगों की जान चली गई और 2,656 नए मामले सामने आए।

उसने बताया कि शनिवार को जिन 89 लोगों की जान गई, उनमें से 81 हुबेई प्रांत के थे, जहां इस विषाणु के कारण सबसे अधिक लोग मारे गए हैं। इसके अलावा दो लोग हेनान में मारे गए। हेबेई, हेइलॉंगजियांग, अनहुइ, शानदोंग, हुनान और गुआंगशी झुआंग में इससे एक-एक व्यक्ति की जान गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्दुआ के अनुसार शनिवार को 600 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई।

डॉक्टर की मौत से चीन में उठी राजनीतिक सुधार की आवाज

कोरोनावायरस के खतरे के प्रति सबसे पहले आगाह करने और इस बात को लेकर सजा पाने वाले एक डॉक्टर की मौत से चीन में राजनीतिक सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग उठने लगी है। वुहान के एक नेत्र चिकित्सक ली वेनलियांग की शुरुवार को मौत हो गई, जिन्होंने एक महीने पहले सार्स जैसे विषाणु के बारे में खुलासा किया था। गौरतलब है कि ली (34) उन आठ चिकित्सकों में एक थे, जिन्हें वुहान पुलिस ने कोरोनावायरस के संबंध में अफवाह फैलाने के लिए दंडित किया था।

ली की मौत के बाद अकादमिक जगत से जुड़े कई लोगों ने चीन में और आजादी की मांग की है। ली की मौत के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते हुए कम से कम दो खुले पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक पत्र पर वुहान के दस प्रोफेसरों ने हस्ताक्षर किए हैं। चीन में ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर इस पत्र को सेंसर किया गया है जिसमें लिखा है कि वेन लियांग के प्रयासों ने देश और समाज के हित को बरकरार रखने का काम किया। इस पत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश को हटाने और डॉ वेन लियांग समेत उन सात अन्य चिकित्सकों से खुलकर माफी मांगने की मांग की गई है, जिन्हें दिसंबर में विषाणु के खतरे के प्रति आगाह करने के लिए दंडित किया गया था। बीजिंग के प्रख्यात शिंहुआ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के एक अनाम समूह द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य पत्र में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को गारंटी देने की मांग उठाई गई है। पत्र में कहा गया है, हम राजनीतिक सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देने का दृढ़ता से विरोध करते हैं। यह किसी छोटे संगठन का बहुत ही स्वार्थी लक्ष्य है। ये पत्र चीन में राजनीतिक सुधार के दुर्लभ आह्वान हैं जहां सरकार से असहमति जताने वालों को जेल भेज दिया जाता है। *एजेंसियां*

नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पोत सवारों को जाने की मंजूरी

कोरोनावायरस संक्रमण की आशंका में हांगकांग में एक पोत पर पांच दिन से रोके गए सैंकड़ों लोगों को रविवार को चालक दल के 1800 सदस्यों की जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद जाने की इजाजत दी गई। हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया था कि चालक दल के 1800 सदस्यों और इतने ही यात्रियों को इस आशंका में पृथक कर दिया गया था कि कुछ कर्मचारी अपनी पिछली जल यात्रा के दौरान वायरस के संपर्क में आए हों और इसका प्रसार कर सकते हों। *एजेंसियां*